नई दिल्ली
गुरुवार
19 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 76
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



आईपीएल 2027 मिनी नीलामी से पहले एलएसजी...पेज-06

DELHIN/2014/58158

प्रधानमंत्री के प्रस्तावित वैशाली दौरे को लेकर...पेज-05

एक नजर

राहुल का कोलंबिया विवि में छात्रों से संवाद, भारत के आर्थिक संकट की ओर बढ़ने का दावा

न्यूयॉर्क,एजेंसी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में मध्यवर्गीय परिवारों के पढ़े-लिखे युवाओं का अपने भविष्य की संभावनाओं से भरोसा उठ रहा है। रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने से युवा निराश हैं और अब वे अपने माता-पिता के अनुभवों और करियर संबंधी सलाह पर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे देश में बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी गंभीर समस्या का संकेत बताते हुए भारत के आर्थिक संकट की ओर बढ़ने का दावा किया। राहुल गांधी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान ये बातें कहीं। कार्यक्रम में उन्होंने अमेरिका की वरिष्ठ पत्रकार लीडिया पोलग्रीन के साथ बातचीत की और इसके बाद छात्रों तथा शिक्षकों के सवालों के जवाब दिए। युवाओं की स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा हालात से निराश युवाओं का एक बड़ा हिस्सा मध्यवर्गीय परिवारों से आता है। इन युवाओं ने औपचारिक शिक्षा हासिल की है लेकिन उन्हें अपने भविष्य की राह दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय का अध्ययन किया जा रहा है और युवाओं की निराशा की एक प्रमुख वजह उन्हें भविष्य में अवसरों की कमी महसूस होना है। राहुल गांधी ने नई और पुरानी पीढ़ी के बीच बढ़ती दूरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युवा अब अपने माता-पिता से कह रहे हैं कि जब उनके पास स्थिर नौकरी या सफलता नहीं है तो वे उन्हें पुराने रास्तों पर चलने की सलाह कैसे दे सकते हैं। युवाओं का मानना है कि पिछली पीढ़ी के लिए काम करने वाले तरीके अब उनके लिए कारगर नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं को इसकी प्रमुख वजह बताया। इन समस्याओं को नजरअंदाज करने से समाधान नहीं निकलेगा।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत-जापान सहयोग और आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण : जयशंकर

टोक्यो,एजेंसी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत तथा जापान के बीच सहयोग को मजबूत करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए आर्थिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने के साथ विश्वसनीय साझेदारियों का विस्तार करना जरूरी है। जयशंकर ने यहां रायसीना टोक्यो 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक व्यवस्था इस समय पांच प्रमुख बदलावों से गुजर रही है। इनमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लगातार मिल रहे झटके, संसाधनों और प्रौद्योगिकी का रणनीतिक इस्तेमाल, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की जरूरत तथा विश्वसनीय साझेदारियों का बढ़ता महत्व शामिल है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, दो बड़े संघर्षों, व्यापारिक व्यवधानों और आर्थिक अस्थिरता ने वैश्वीकरण के दशकों के दौरान विकसित हुई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। ऊर्जा, संसाधन, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे क्षेत्रों का तेजी से रणनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की मोदी ने, योजनाओं और कामकाज पर हुई चर्चा



नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की प्रत्येक योजना और नीति के केंद्र में देश की जनता होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सीधे, पारदर्शी और सरल तरीके से पहुंचे। प्रधानमंत्री यह महत्वपूर्ण बैठक अपने दो दिवसीय फिलीपींस दौरे से लौटने के कुछ ही घंटों बाद की। प्रधानमंत्री ने 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि सुशासन का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब सरकार की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को बिना किसी परेशानी और अनावश्यक बाधा के मिले। इसके लिए सभी मंत्रालयों को अपनी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान सितंबर में आयोजित मंत्रिपरिषद के चिंतन शिविर में निर्धारित लक्ष्यों और कार्ययोजनाओं की प्रगति का फीडबैक लिया।

उन्होंने मंत्रियों से पिछली बैठक के बाद हुए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा मांगा तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में सितंबर में आयोजित चिंतन शिविर के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान तीन महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं और विभिन्न योजनाओं की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। इनमें गरीबी उन्मूलन और वामपंथी उग्रवाद के खात्मे से संबंधित विषय भी प्रमुख रूप से शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति का आकलन करते हुए आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की। बैठक का मूल उद्देश्य सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक जवाबदेही और आम जनता तक विकास का लाभ सुनिश्चित करना रहा। इस महत्वपूर्ण बैठक में विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए तैयार किए जा रहे रोडमैप पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। इसी उद्देश्य से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतियों पर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि सितंबर में आयोजित चिंतन शिविर के बाद विजनञ्ज2047 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से सचिवों के 10 सेक्टोरल समूहों का गठन किया गया था। इन समूहों ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है। बैठक में इन समूहों की ओर से किए गए कार्यों और तैयार किए जा रहे रोडमैप की प्रगति का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने इस बात पर विचार किया कि निर्धारित लक्ष्य की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और आने वाले समय में किन क्षेत्रों में तेजी से काम करने की आवश्यकता है।

गाजियाबाद जेल से रिहा हुए सपा नेता आज़म खान

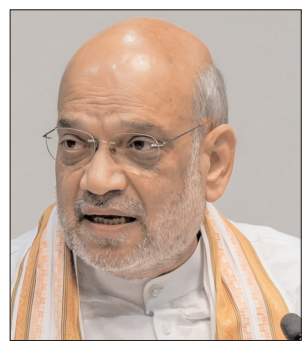
गाजियाबाद,एजेंसी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद रहे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को आज गाजियाबाद के डासना जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सपा नेता बुधवार शाम को जेल से बाहर आए। उन्होंने अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जेल से निकलते ही वह सीधे गाड़ी में बैठकर रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को अपनी कार में लेकर रामपुर के लिए निकले। इस दौरान आजम खान के समर्थक बेहद बेकाबू नजर आए। उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह गाजियाबाद के सीजीएम कोर्ट में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा हुए। इस मामले में ईडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।



आजम खान के रिहाई के बाद उनके बेटे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें पिछले आठ सालों से भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के मामले में सजा हुई है। जो हमारे साथ हुआ, वह किसी के साथ नहीं हुआ। आजम खान को 10 साल की सजा टीवी चोरी करने नहीं करवाने के आरोप में हुई और उस जगह की सजा हुई जहां पर कोई घर ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं पिछले सात सालों से इस बात की सजा काट रहा हूं कि गलत जन्मतिथि ठीक क्यों करवा ली। उन्होंने कहा कि मैं इसको साबित नहीं कर सका, क्योंकि मेरा नाम अब्दुल्ला है। अगर मैं अब्दुल्ला नहीं होता तो शायद साबित कर देता। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम इतनी बेइज्जती और जिल्लत के बाद भी जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि एक 80 वर्ष के इंसान को जिसने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति में बिता दी। उन्होंने कहा कि आजम खान 10 बार एमएलए और दो बार एमपी रहे। उनसे एक गलती हुई कि उन्होंने बच्चों के पढ़ने का इंतजाम किया। उस रामपुर के लिए जिसका शिक्षा का औसत 22 प्रतिशत था। उन्होंने यह सपना देखा कि उनके शहर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर वह यूनिवर्सिटी का ख्वाब नहीं देखे होते और अन्य विधायक और सांसदों जैसा ही किया होता तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमें, हमारे नाम की सजा मिली। अगर हमारा नाम आजम खान और अब्दुल आजम खान नहीं होता तो शायद यह हमारे साथ नहीं होता। यह एक सच्चाई है। आजम खान की रिहाई पर उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने कहा कि मुझे हमेशा अल्लाह पर बहुत भरोसा रहा कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। जिस तरह आजम साहब को जेल के गेट से ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ले गई, वह शायद जुल्म की आखिरी हद थी। मुझे भरोसा था कि न्याय मिलेगा।

कश्मीर घाटी में लश्कर का आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट मारा गया: अमित शाह

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट को मार गिराया है। उन्होंने उसे कश्मीर घाटी में लश्कर का आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकवादी बताया। अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और खुफिया एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से बुधवार तड़के कुलगाम में अभियान चलाकर लतीफ भट को मार गिराया गया। उसका एक आतंकवादी सहयोगी उमर निसार भी इससे एक दिन पहले कुलगाम में मारा गया था। उन्होंने कहा कि पूरा अभियान सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहद उच्च स्तर के तालमेल का उदाहरण रहा। गृह मंत्री ने इस अभियान में शामिल जम्मू-कश्मीर



पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के जवानों के साहस की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र उनके शौर्य को सलाम करता है। इस बीच, कश्मीर जोन पुलिस ने बुधवार सुबह 'एक्स' पर बताया कि मुठभेड़ स्थल से मारे गए एक आतंकवादी का शव और हथियार बरामद किया गया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान कुलगाम के खेवां निवासी मोहम्मद लतीफ भट के रूप में की गई है। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने भी अभियान के बाद जवानों को बधाई दी। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'बधाई हो दोस्तों। कुछ व्यंजन ठंडे परोसे जाने पर ही बेहतर लगते हैं, ठंडे मौसम में भी।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय लतीफ भट पहले बढ़ई का काम करता था और उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह 11 नवंबर को कुलगाम में सीआरपीएफ के एक जांच नाके पर हुए हमले में कथित रूप से शामिल था, जिसमें तीन जवान घायल हुए थे। बताया जाता है कि अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने लतीफ भट को आत्मसमर्पण करने के कई अवसर दिए। उसे वीडियो कॉल के जरिए भी समझाने का प्रयास किया गया लेकिन उसके आत्मसमर्पण नहीं करने पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। वह एक मस्जिद में छिपा हुआ था, जहां से उसे बाहर निकालने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया।

अंडमान-निकोबार में जेल प्रशासन के लिए नया कानून, औपनिवेशिक दौर के तीन अधिनियम निरस्त होंगे

नई दिल्ली,एजेंसी। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में जेल प्रशासन को औपनिवेशिक दौर की दंड केंद्रित व्यवस्था से निकालकर मानवीय और सुधारोन्मुख बनाने के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत 'अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विनियमन, 2026' जारी किया है। इसके तहत 1894 के कारागार अधिनियम सहित तीन पुराने कानूनों को निरस्त कर कैदियों की सुरक्षा, गरिमा, सुधार और पुनर्वास से जुड़े प्रावधान लागू किए जाएंगे।

सूत्रों के मुताबिक, यह विनियमन 17 नवंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसके तहत कारागार अधिनियम, 1894, बंदी अधिनियम, 1900 और बंदियों के स्थानांतरण अधिनियम, 1950 निरस्त होंगे। हालांकि, नए प्रावधान उस तारीख से लागू होंगे, जिसे अंडमान-निकोबार के प्रशासक राजपत्र में अधिसूचित करेंगे। पुराने कानूनों के तहत जारी नियम और



आदेश नए विनियमन के विपरीत नहीं होने की स्थिति में तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक उनमें बदलाव नहीं किया जाता। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि नए कानून का उद्देश्य जेलों को केवल कैद और सजा की जगह के बजाय सुधार एवं पुनर्वास के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसमें खुली और अर्ध-खुली सुधारात्मक संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। कैदियों के लिए उनकी जरूरतों के अनुरूप व्यक्तिगत सजा एवं पुनर्वास योजना तैयार करने, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। कैदियों का वर्गीकरण उनकी उम्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी जोखिम और सुधारात्मक जरूरतों के आधार पर होगा। जेलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक पहचान, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली (आरएफआईडी), डिजिटल अभिलेख, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल नेटवर्क बाधित करने वाली तकनीक के इस्तेमाल का प्रावधान है। जेलों के भीतर अनधिकृत मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण रखने या इस्तेमाल करने पर तीन साल तक की कैद अथवा 25 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी के समुद्री टोही अभियानों के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय नौसेना अपनी लंबी दूरी के समुद्री टोही अभियानों की स्वर्ण जयंती का उत्सव मना रही है। इन पांच दशकों में नौसेना ने भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए हवाई निगरानी और सतर्कता के जरिए बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान भारतीय नौसेना के विमानों ने ऑपरेशन कैक्टस, विजय, पराक्रम और सिंदूर सहित कई महत्वपूर्ण अभियानों के साथ-साथ समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और खोज एवं बचाव मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय नौसेना ने बुधवार को अपनी लंबी दूरी के समुद्री टोही अभियानों के पांच दशक पूरे किये हैं। दरअसल,

- सुपर कॉन्स्टेलेशन से पी-8आई तक समुद्री निगरानी में भारतीय नौसेना की पांच दशक लंबी यात्रा



पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के बाद नौसेना को ऐसे तट-आधारित समुद्री गश्ती विमानों की आवश्यकता महसूस हुई, जो युद्धपोतों और हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर काम कर सकें। इसके बाद भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की समुद्री टोही की जिम्मेदारी संभाली। 18 नवंबर, 1976 को गोवा स्थित आईएनएस हंसा में आईएनएएस 312 की स्थापना की गई, जिसे 'अल्बाट्रॉस' के नाम से जाना जाता है।

इस स्क्वाड्रन को भारतीय वायु सेना से हस्तांतरित किए गए पांच लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन विमानों से लैस किया गया था। भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए पांच दशकों से जारी हवाई निगरानी और सतर्कता का प्रतीक है। वर्ष 1977 में इल्यूशिन ङ्घद्य-38 विमानों को शामिल किए जाने से नौसेना की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता मजबूत हुई।

देश से मोहब्बत ही सबसे बड़ा राष्ट्रवादः वजाहत हबीबुल्ला

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किया राष्ट्रवाद की नई परिभाषा विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन

नई दिल्ली,एजेंसी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दिल्ली में राष्ट्रवाद की नई परिभाषा विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित भारत के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि देश से मोहब्बत ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। उन्होंने कहा कि हम जिस देश में रहते हैं हम उस देश के नागरिक हैं और हम संविधान पर अमल करते हैं और सभी से मिलजुल कर रहते हैं तो यही राष्ट्रवाद है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ा नफरत का माहौल जो बना वह बंटवारे की वजह से बना। हमारे देश को हिंदू और मुसलमान राष्ट्रों में बांट दिया गया और इसके बाद जो हुआ उसकी आंच आज तक हमें देखने को मिल रही है। इस मौके पर प्रख्यात चिंतक विचारक योगेंद्र यादव, सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, विधायक इमरान हुसैन,



कौसर हयात, आसिफ अन्सारी, खुर्रम ओ उमर, मौलाना निसार अहमद आदि ने भाग लिया। वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि इस देश को बनाने में सभी का योगदान है, लेकिन आज कुछ लोग सारा श्रेय लेना चाहते हैं जो सही नहीं है। उन्होंने अपने गांव का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा गांव बाराबंकी जिला में है और यहां की आबादी मुस्लिम बहुल है। हमारा गांव आज तक टाउन नहीं बन पाया। सिर्फ मुस्लिम आबादी की वजह से इसे यह दर्द झेलना पड़ रहा है। इस अवसर पर योगेंद्र यादव ने कहा की आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं इसका सीधा-साधा संदेश यह है कि हमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय के राष्ट्रवाद को अपनाने के लिए सभी को प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि उस समय का राष्ट्रवाद सभी को जोड़ने वाला था। उन्होंने कहा कि 100 साल से आरएसएस हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का जो नारा लेकर राष्ट्रवाद की परिभाषा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है हमें यह राष्ट्रवाद नहीं चाहिए हमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा वाला राष्ट्रवाद चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्रवाद की हमें जरूरत नहीं है जो दो भाइयों को आपस में लड़ाने वाला हो। उन्होंने बताया कि इस वक्त जो राष्ट्रवाद जर्मनी से आयात किया गया है हमें जर्मनी का राष्ट्रवाद नहीं चाहिए हमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय वाला राष्ट्रवाद चाहिए।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) में उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में प्रदूषण हॉटस्पॉट, निगरानी व जांच, कार्रवाई, सड़कों और निर्माण स्थलों की धूल, वाहनों व सार्वजनिक परिवहन से होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण एवं तोड़फोड़ के कचरे और ठोस कचरे के निस्तारण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समन्वय, जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अधिक और कम, दोनों एक्यूआई वाले क्षेत्रों में नियमित निगरानी करने के निर्देश दिया है। बैठक में हॉटस्पॉट के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कों, कच्चे हिस्सों और गड्ढों से संबंधित लंबित शिकायतों की जोनवार एवं विभागवार समीक्षा भी की गई। विभिन्न एजेंसियों से संबंधित कुल 68,137 शिकायतों में से 61,507 का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने संबंधित विभागों को लंबित गड्ढों और कच्ची सड़कों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।



मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए केवल ग्रीन नेट लगाने की औपचारिकता न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन नेट निर्धारित मानकों के अनुसार स्कैफोल्डिंग के साथ सही तरीके से लगाया जाए। संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने सड़क खुदाई के बाद लंबे समय तक सड़कें क्षतिग्रस्त छोड़ने पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस विभाग या एजेंसी ने सड़क खोदी है, वही काम पूरा होने के बाद सड़क को पहले जैसी स्थिति में बहाल करेगी। मुख्यमंत्री ने सड़कों से धूल, मिट्टी और गाद नियमित रूप से हटाने तथा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों, पानी के छिड़काव और सड़क धुलाई से धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में सीएक्यूएम के तहत सड़क पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की गई। वर्ष 2026 में 3,744 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास की जरूरत चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 10 दिसंबर से लागू निर्माण एवं ध्वस्तीकरण प्रतिबंधों के दौरान जरूरी सड़क और जनसुविधा संबंधी कार्य अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों। संबंधित एजेंसियां नियमों और अनुमति छूट के अनुसार काम जारी रखें ताकि प्रदूषण नियंत्रण के साथ विकास कार्य भी चलते रहें। दिल्ली मेट्रो को अपने क्षेत्र में उपलब्ध एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट स्प्रे सिस्टम शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक नियमित चलाने को कहा गया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस वर्ष अब तक एक भी गंभीर प्रदूषण वाला दिन दर्ज नहीं हुआ और एक्यूआई 400 के पार नहीं पहुंचा, जबकि पिछले दस वर्षों में नवंबर में अक्सर 4 से 6 दिन ऐसा होता था। नवंबर के पहले पखवाड़े में औसत एक्यूआई लगभग 170 रहा, अक्टूबर पिछले दशक का सबसे बेहतर महीना रहा और साफ हवा वाले दिनों की संख्या रिकॉर्ड 220 तक पहुंची। यमुना सफाई और कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण में भी करीब 60 प्रतिशत सफलता मिली है। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में विभागों की कार्ययोजना और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा कर सड़क की धूल, निर्माण कार्य और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए तत्काल उपायों के साथ दीर्घकालिक रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है और दोपहिया, तिपहिया व चारपहिया वाहनों को भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बाहरी वाहनों की फिटनेस और उत्सर्जन पर निगरानी रखी जाएगी। पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

फिल्म 'सूर्या' के ट्रेलर और फिल्म में लगेगा डिस्क्लेमर, दिल्ली हाई कोर्ट में निर्माताओं ने दिया भरोसा

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। सनी देओल अभिनीत हिंदी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को लेकर डॉक्टरों की आपत्तियों के बाद फिल्म निर्माता इसके ट्रेलर और फिल्म में डिस्क्लेमर शामिल करेंगे। निर्माताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि डिस्क्लेमर में स्पष्ट किया जाएगा कि फिल्म काल्पनिक रचना है और मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का रूपांतरण है। इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए न्यायमूर्ति अमित महाजन की बेंच ने 17 नवंबर को याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि इस मामले में अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

डॉ. निशांत सोनी और अन्य डॉक्टरों की ओर से दायर याचिका में फिल्म के टीजर और ट्रेलर पर आपत्ति जताई गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फिल्म में निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों के डॉक्टरों को भ्रष्ट तरीके से दिखाया गया है। इससे चिकित्सा पेशे की गलत छवि बन सकती है और पहले से ही हिंसा का सामना कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ने की आशंका है। डॉक्टरों ने यह भी दलील दी थी कि फिल्म के टीजर में कहानी को 'अविश्वसनीय सच्ची घटनाओं से प्रेरित' बताने से दर्शकों के बीच यह धारणा बन सकती है कि इसमें दिखाई गई घटनाएं वास्तविक हैं। याचिका में संबंधित अधिकारियों को टीजर की जांच करने और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टीजर हटाने या उस पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी।

निर्माता एमएम मूवीज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने न्यायालय को बताया कि 'सूर्या' वर्ष 2018 में आई मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का रूपांतरण है। उन्होंने कहा कि मूल फिल्म पर किसी प्राधिकरण ने प्रतिबंध नहीं लगाया था और उसे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिले हैं। निर्माताओं की ओर से ट्रेलर और पूरी फिल्म में उपयुक्त डिस्क्लेमर लगाने का आश्वासन दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि उस समय तक फिल्म को प्रमाणन की अनुमति नहीं मिली थी। न्यायालय ने निर्माता के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। फिल्म पहले 20 नवंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, सेंसर प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा में निर्माताओं ने इसकी रिलीज टाल दी है।

रेजांगला शौर्य दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया वीरों को नमन

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में 'रेजांगला शौर्य एवं यदुकुल सम्मान दिवस' में शामिल होकर मां भारती के अमर वीर सपूतों को नमन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन कृष्ण यादव महासभा ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1962 में रेजांगला की बर्फीली पहाड़ियों पर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वीर जवानों ने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया।

उन्होंने कहा कि 114 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन आखिरी सांस तक दुश्मन के सामने डटे रहे। रेजांगला का शौर्य हमें याद दिलाता है कि मां भारती की आन, बान और शान से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र इन वीरों का सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर दिवाली अपने सैनिकों के साथ मनाते है। आज सैनिकों को सभी सुविधाएं और हथियार तुरंत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा पहले सेना को जवाब देने के लिए दिल्ली के आदेशों को घंटों इंतजार करने पड़ता था, आज दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारते हैं। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष राजेश यादव, हरियाणा विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष संतोष यादव उपस्थित रहे। सांसद अरुण सिंह ने कहा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांगला की वीरभूमि पर अहिर वीरों ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया।

क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2027 में डीयू की बड़ी छलांग, भारत में तीसरे और दुनिया में 237वें स्थान पर

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स: सस्टेनेबिलिटी 2027 में अपनी स्थिति में सुधार करते हुए भारत में तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं, वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय 237वें और एशिया में 30वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष की रैंकिंग में डीयू वैश्विक स्तर पर 241वें, एशिया में 36वें और भारत में चौथे स्थान पर था।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बुधवार को बताया कि विश्वविद्यालय का कुल स्कोर भी पिछले वर्ष के 80.9 से बढ़कर इस बार 84.2 हो गया है। नवीनतम रैंकिंग में दुनिया भर के 2,004 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिनमें एशिया के 850 और भारत के 100 संस्थान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने चार प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों- पर्यावरण शिक्षा, ज्ञान का आदान-प्रदान, शिक्षा का प्रभाव और सुशासन में भारत में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति शैक्षणिक उत्कृष्टता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और समाज पर सार्थक प्रभाव डालने के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत में तीसरा स्थान और चार प्रमुख संकेतकों में पहला स्थान हासिल करना विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और टिकाऊ संस्थान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रो. सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय स्थिरता केंद्रित शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करने, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने, परिसर में पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में अपना योगदान बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करेगा। रैंकिंग के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय ने पर्यावरण प्रभाव और सामाजिक प्रभाव की श्रेणियों में भी अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, जबकि सुशासन के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन बरकरार रखा है। पर्यावरण प्रभाव श्रेणी में विश्वविद्यालय का स्कोर 80.6 से बढ़कर 84.3 हो गया है। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में डीयू ने वैश्विक रैंकिंग में 53वें से 51वें स्थान पर पहुंचकर 95.7 के स्कोर के साथ भारत में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, पर्यावरण अनुसंधान में विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग 616वें से सुधरकर 590वें स्थान पर पहुंच गई है। पर्यावरण स्थिरता का स्कोर भी 64.4 से बढ़कर 71.9 हो गया है।

नीट-यूजी पेपर लीक केस में 14 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

नई दिल्ली,एजेंसी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 14 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने आरोप तय करते हुए इस मामले पर 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने भारतीय न्यायिक संहिता , प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मिन्स एक्ट के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया उनमें यश यादव , मांगीवाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रह्लाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे, मनीषा संजय हवलदार और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी शामिल हैं। कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 29 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10 ,धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू की गई। सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में दाखिले होंगे अब क्यूआर कोड से, तीन हजार सफाईकर्मी-चौकीदारों की भर्ती प्रक्रिया भी तेज

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में दाखिले बढ़ाने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत निगम के प्रत्येक स्कूल के बाहर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, ताकि अभिभावक घर बैठे दाखिले के लिए पंजीकरण करा सकें। वहीं, स्कूलों में सुरक्षा और सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए करीब 3,000 सफाईकर्मियों और चौकीदारों की भर्ती की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।



दिल्ली नगर निगम शिक्षा समिति की बैठक बुधवार को समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में एडिशनल कमिश्नर संजीव मित्तल, शिक्षा निदेशक आयुषी, समिति के सदस्य पार्षद और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निगम के स्कूलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण तथा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए दाखिला अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने एक से 15 नवंबर तक की दाखिला रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें दिवाली की छुट्टियों के बावजूद दाखिला प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी दी गई। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि प्रत्येक निगम स्कूल के बाहर क्यूआर कोड लगाया जाए। अभिभावक इसे स्कैन कर अपना विवरण दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक उनसे संपर्क कर दाखिले की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके अलावा निगम के एजुलाइफ पोर्टल पर भी ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए सिविक सेंटर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को संबंधित क्षेत्र के नजदीकी स्कूलों में भेजेगा। इसके बाद स्कूल प्रशासन अभिभावकों से संपर्क कर दाखिले की कार्रवाई करेगा। स्कूलों में सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा समिति अध्यक्ष ने एडिशनल कमिश्नर को करीब 3,000 सफाईकर्मियों और चौकीदारों की भर्ती से संबंधित फाइल एक सप्ताह के भीतर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही लंबे समय से कार्यरत चौकीदारों के नियमितीकरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने को कहा गया। बैठक में निगम के स्कूलों के पार्कों और खेल मैदानों की स्थिति सुधारने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए उद्यान विभाग को निर्देश दिए गए कि वार्डों की तर्ज पर स्कूलों के पार्कों और मैदानों के रखरखाव के लिए यार्डस्टिक के अनुसार कर्मचारियों और मालियों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार भेजा जाए। वहीं, स्कूलों को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए शुरुआती चरण में 250 निगम स्कूलों का चयन किया गया है।

दिल्ली की पांच भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन, कपिल मिश्रा सभी के अध्यक्ष

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने पांच प्रमुख भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया है। यह पहल राजधानी की विविध भाषाई विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा की स्वीकृति से किए गए इस पुनर्गठन के अंतर्गत हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी, गढ़वाली, कुमाऊंनी एवं जौनसारी अकादमी, मैथिली-भोजपुरी अकादमी तथा पंजाबी अकादमी की गवर्निंग काउंसिल का नए सिरे से गठन किया गया है। मंत्री कपिल मिश्रा इन सभी पांचों अकादमियों के अध्यक्ष होंगे। पांचों अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल में कुल 101 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य अकादमियों के कामकाज में नई ऊर्जा, बेहतर प्रशासनिक समन्वय और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन सुनिश्चित करना है। अधिसूचना के अनुसार, पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल जारी होने की तिथि से दो वर्ष का होगा।

अकादमीवार सदस्यों की संख्या एवं उपाध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है:-

हिंदी अकादमी: कुल 20 सदस्य, जिनमें एक उपाध्यक्ष श्री अनिल अग्रवंशी, 15 मनोनीत सदस्य, दो पदेन सदस्य तथा सदस्य सचिव शामिल हैं।

संस्कृत अकादमी : कुल 18 सदस्य, जिनमें एक उपाध्यक्ष प्रो. यशवीर सिंह, 13 मनोनीत सदस्य, दो पदेन सदस्य तथा सदस्य सचिव शामिल हैं।

गढ़वाली, कुमाऊंनी एवं जौनसारी अकादमी : कुल 17 सदस्य, जिनमें एक उपाध्यक्ष डॉ. धीरज जोशी, 12 मनोनीत सदस्य, दो पदेन सदस्य तथा सदस्य सचिव शामिल हैं।

मैथिली-भोजपुरी अकादमी : कुल 22 सदस्य, जिनमें एक उपाध्यक्ष बिपिन बिहारी, 17 मनोनीत सदस्य, दो पदेन सदस्य तथा सदस्य सचिव शामिल हैं।

पंजाबी अकादमी : कुल 24 सदस्य, जिनमें एक उपाध्यक्ष सरदार इम्प्रीत सिंह बख्शी, 19 मनोनीत सदस्य, दो पदेन सदस्य तथा सदस्य सचिव शामिल हैं।

वकीलों को कथित धमकी मामले में गृह मंत्रालय और निलंबित एसीपी को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस कर्मियों द्वारा वकीलों को कथित रूप से धमकाने के मामले में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय और निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे उन आपत्तिजनक वीडियो की जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वे 48 घंटे के भीतर संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया खातों का विवरण केंद्र सरकार को सौंपें। न्यायालय ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के साथ-साथ सब-इंस्पेक्टर विशाल यादव को भी नोटिस जारी किया है। सब-इंस्पेक्टर पर वकीलों के खिलाफ एके-47 राइफल के इस्तेमाल की धमकी देने का आरोप है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अनुशासनहीनता के आरोप में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को 2 नवंबर को ही निलंबित किया जा चुका है। मंत्रालय के समक्ष उनके खिलाफ आरोपपत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। वकील करण बीर सिंह द्वारा दायर याचिका में वकीलों की सुरक्षा, गरिमा और पेशेवर स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2 नवंबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए पुलिस प्रदर्शन के दौरान एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और अन्य कर्मियों ने वकीलों के खिलाफ अपमानजनक और धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया। यह पूरा विवाद 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प से शुरू हुआ था। उस घटना के बाद अधिकारियों के तबादले के विरोध में 2 नवंबर को पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन किया था।

मानहानि मामले में कोर्ट में पेश हुए सौरभ भारद्वाज, तीन दिसंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शिकायतकर्ता के वकील को निर्देश दिया कि वे आरोपितों को शिकायत की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराएं। यह शिकायत 'गुल्लक चोरी', चावल चोरी और करोड़ों रुपये के घोटाले से जुड़ी कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज कराई गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने 29 अक्टूबर को न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और कुलदीप कुमार के लगाए गए आरोप निराधार और उनके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं। सिरसा ने कहा कि ये नेता इससे पहले भी इसी तरह के निराधार आरोप लगाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मनजिंदर सिंह सिरसा पर गुरुद्वारे की गुल्लक के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और उन्हें 'गुल्लक चोर' कहा था। सिरसा ने न्यायालय में कहा कि सिख धर्म में गुल्लक का बेहद पवित्र स्थान है और इस तरह के शब्दों से उनकी सामाजिक व धार्मिक प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची है।

पोते ने 87 वर्षीय रिटायर्ड नौसेना अधिकारी के खाते से उड़ाए 29.50 लाख रुपये, दोस्त समेत गिरफ्तार

नई दिल्ली,एजेंसी। पूर्वी जिला के साइबर थाना पुलिस ने 87 वर्षीय सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी के बैंक खाते से 29 लाख 50 हजार 892 रुपये की ठगी के आरोप में उनके पोते और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पोते पर आरोप है कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बुजुर्ग के बैंक खाते से जुड़ी जानकारी का दुरुपयोग कर रकम अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित कर ली। ठगी की रकम से दोनों ने महंगी यात्राएं कीं, दोस्तों के साथ पार्टियां कीं और अपने शौक पूरे किए। इसी रकम से 2.75 लाख रुपये में एक पोलो कार भी खरीदी। पुलिस ने कार और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं।



पुलिस के अनुसार, इस मामले में अश्वनी राघव ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके 87 वर्षीय पिता जगदीश सिंह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हैं। अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच उनके बैंक खाते से लगातार धोखाधड़ी कर रकम निकाली गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ई-एफआईआर संख्या 450/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि खाते से कुल 29,50,892 रुपये निकाले गए थे। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 319 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक पवन यादव के नेतृत्व में एएसआई शिव कुमार, हेड कांस्टेबल अनुराग और हेड कांस्टेबल योगेश की टीम गठित की गई। एसीपी ऑपरेशन महावीर प्रसाद की निगरानी में पुलिस टीम ने बैंक रिकॉर्ड, केवाईसी दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच की। जांच में पता चला कि ठगी की रकम में से 9,26,892 रुपये अभिषेक राघव के नाम पर खुले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाते में स्थानांतरित किए गए थे। वहीं, 20,24,000 रुपये तुषार चौधरी के पंजाब नेशनल बैंक खाते में भेजे गए थे। बैंक खातों और लेनदेन की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने दोनों आरोपितों की पहचान की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर अभिषेक राघव और तुषार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 22 वर्षीय अभिषेक राघव शिकायतकर्ता अश्वनी राघव का बेटा और पीड़ित बुजुर्ग का पोता है। उसका मोबाइल नंबर दादा के बैंक खाते से जुड़ा हुआ था। आरोप है कि उसने इसी जानकारी का फायदा उठाकर अपने दोस्त तुषार चौधरी के साथ ठगी की साजिश रची और खाते से रकम अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित कराई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बाकी रकम किन खातों में भेजी गई और इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपितों ने ठगी की रकम मौज-मस्ती और शौक पूरे करने में खर्च की। दोनों मनाली, नैनीताल और ओडिशा घूमने गए। इसके अलावा नोएडा में दोस्तों के साथ पार्टियां कीं। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने ठगी की रकम से 2.75 लाख रुपये में एक पोलो कार खरीदी थी। कार में 1.25 लाख रुपये का म्यूजिक सिस्टम भी लगवाया था। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। दोनों के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार अभिषेक राघव खुर्जा से बीए-एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। वहीं, दूसरा आरोपित तुषार चौधरी भी 22 वर्ष का है और खुर्जा से नर्सिंग का कोर्स कर रहा है। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एक नजर

एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर ठग लिए 30 लाख रुपये

गुरुग्राम। एमबीबीएस कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई। खास बात यह है कि यह धोखाधड़ी कोई ऑनलाइन तरीके से नहीं बल्कि एक महंगी जगह पर कार्यालय खोलकर की गई। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने इस धोखाधड़ी में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 16 नवंबर 2026 को एक व्यक्ति ने थाना सदर गुरुग्राम में धोखाधड़ी की एक शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि दा एडमिश सॉल्यूशन जेएमडी मेगा पोलिस सेक्टर-48 गुरुग्राम से संचालित होता है। उसने अपने बेटे का एमबीबीएस में एडमिशन कराने के लिए दा एडमिश सॉल्यूशन को 30 लाख रुपए दिए थे। जब वह अलॉटमेंट लेटर लेने गया तो उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस शिकायत पर थाना सदर गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया। जांच के बाद थाना सदर गुरुग्राम की पुलिस टीम ने इस धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान बंटी कुमार तिवारी निवासी जिला गोपालगंज बिहार, अभिषेक आनंद निवासी पटना बिहार, मोहम्मद जुबेर निवासी हौजरानी, मालवीय नगर, जिला दक्षिण दिल्ली के रूप में हुई है। प्राथमिक पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी एमबीबीएस में एडमिशन दिलवाने के नाम पर रुपये लेकर लोगों से ठगी करते थे। आरोपियों के विरुद्ध पश्चिम बंगाल, पंजाब सहित अन्य जगहों पर इसी प्रकार धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं।

निवेश के नाम पर ठगी के लिए साइबर ठगों को बैंक खाता दिया, एक काबू

गुरुग्राम। निवेश के नाम पर ठगी करने के लिए साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराने का एक आरोपी पुलिस के कब्जे में आया है। कुल ठगी गई राशि में से दो लाख 50 हजार रुपये आरोपी मुस्ताक के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि साइबर अपराध दक्षिण थाना में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार 19 नवंबर 2025 को एक व्यक्ति ने थाना साइबर अपराध दक्षिण गुरुग्राम में शिकायत दी कि निवेश के नाम पर उससे 12 लाख 44 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। इस शिकायत पर थाना साइबर अपराध दक्षिण में केस दर्ज करके जांच की गई। पुलिस टीम ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मुस्ताक अहमद निवासी मुसलिंघोपा जिला दरंग असम के रूप में हुई है। पुलिस जांच व पूछताछ में पता चला कि ठगी गई राशि में से दो लाख 50 हजार रुपये आरोपी मुस्ताक के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी। वह बैंक खाता आरोपी मुस्ताक ने कमीशन पर एक अन्य व्यक्ति को बेचा था।

गाजियाबाद में खराब मिठाई देने का आरोप लगा तीन बाउंसर लेकर दुकान पहुंचा युवक

गाजियाबाद। गोविंदपुरम इलाके में तीन बाउंसरों के साथ मिठाई की दुकान पर पहुंचे युवक ने व्यापारी से मारपीट कर दी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। गोविंदपुरम में मिठाई की दुकान से एक युवक ने दीपावली पर मिठाई खरीदी। उसने मिठाई गिफ्ट कर दी थी। युवक का आरोप है कि उसे खराब मिठाई थमा दी गई। जिससे उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई है। युवक तीन बाउंसरों के साथ दुकान पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में युवक गाली देते और बाउंसर के साथ व्यापारी पर हमला करता दिख रहा है। विरोध करने पर एक बाउंसर ने व्यापारी का हाथ पकड़ लिया और पूरी तरह आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। पीड़ित दुकानदार द्वारा गलती स्वीकार करने और स्थिति संभालने की कोशिश करने के बावजूद दबंगई दिखा रहे युवकऔर उनके साथ आए बाउंसरों ने उसे गंदी-गंदी गालियां दीं और मारपीट पर उतारू हो गए। मामले में एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि पीड़ित व्यापारी की शिकायत लेकर फुटेज के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

अब गड्ढा नहीं भरा जाएगा, नोएडा में एलिवेटेड रोड का हिस्सा ही बदलेगा

नोएडा। शहर की पहली एलिवेटेड रोड पर बार-बार गड्ढा होने की वजह शुरुआती तकनीकी जांच में सामने आई है। एमपी-टू स्थित सेक्टर 27-28 से सेक्टर 60-61 तक बनी इस सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से में बेयरिंग कमजोर पाई गई है। पर्याप्त भार न संभाल पाने के कारण एक सेगमेंट पर दबाव पड़ा और उसमें दरारें आ गईं। इसका असर करीब 11 मीटर लंबे हिस्से पर हुआ, जिसकी ऊपरी सतह क्षतिग्रस्त होकर गड्ढे में बदल गई। बता दें कि सेक्टर-61 से सेक्टर-18 की ओर जाने वाली लेन में सेक्टर-33 स्थित इस्कॉन मंदिर के सामने 18 अक्टूबर को पहली बार गड्ढा हुआ था। मरम्मत के बाद 20 अक्टूबर को उसी जगह फिर गड्ढा बन गया। सुरक्षा के मद्देनजर 21 अक्टूबर को लेन पर यातायात बंद कर दिया गया। यह लेन 26 दिन से बंद है और नीचे की सड़क पर दबाव बढ़ा है। एमपी-टू एलिवेटेड रोड प्रीकास्ट तकनीक से बनी है। इसमें पहले से तैयार कंक्रीट के हिस्सों को मौके पर जोड़कर लगाया जाता है।

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग: बागपत के छह युवा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित

बागपत,एजेंसी। विकसित भारत का सपना और उसे साकार करने के लिए युवाओं की सोच बुधवार को बागपत में आयोजित जनपद स्तरीय चैंपियनशिप में देखने को मिली। विकास भवन सभागार में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2027 में करीब नौ हजार युवाओं ने प्रतिभाग किया। विभिन्न चरणों के बाद छह युवाओं का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। ये युवा लखनऊ में बागपत का प्रतिनिधित्व करेंगे।



युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देश पर आयोजित प्रतियोगिता के क्विज राउंड में करीब नौ हजार और निबंध प्रतियोगिता में 900 युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से चयनित 46 प्रतिभागियों ने फाइनल राउंड में विकसित भारत से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर शिवम, आर्यवर्त त्यागी, गुनगुन शर्मा, कुणाल चौहान, अदिति तोमर और दीक्षा को राज्य स्तर के लिए चुना गया। मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने युवाओं के विचारों की सराहना करते हुए उन्हें जनपद के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में एआई और मौलिक चिंतन के महत्व पर विशेष चर्चा हुई। शिक्षाविद् डॉ. सत्यवीर सिंह ने कहा कि एआई के दौर में तकनीक सीखना जरूरी है, लेकिन अपनी मौलिक सोच बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तकनीक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, उसके गुलाम न बनें। उन्होंने युवाओं को विषय की गहरी समझ, नियमित अभ्यास और प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना स्थानीय समस्याओं के समाधान से जुड़ी होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन की चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान ही वास्तविक विकास का आधार हैं। उल्लेखनीय है कि इस संवाद के राष्ट्रीय महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं के विचार सुनते हैं। जनवरी 2026 में बागपत के युवा अमन कुमार ने टीम यूपी के ग्रुप कैप्टन के रूप में 79 युवाओं का नेतृत्व कर प्रदेश में जिले का नाम रोशन किया था। इस अवसर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सोनू कुमार, शिप्रा सिंह, जिला युवा अधिकारी अनिकेत शर्मा, पूर्व ग्रुप कैप्टन अमन कुमार तथा निर्णायक मंडल के सदस्य डॉ. सत्यवीर सिंह, डॉ. गीता और तनु सूर्यान मौजूद रहे।

बैड कैरेक्टर अपराधियों को हर 15 दिन में थाने में लगानी होगी हाजिरी

गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने तथा आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बुधवार को पुलिस उपायुक्त पश्चिम शशि शेखर के नेतृत्व में थाना पालम विहार, उद्योग विहार तथा सेक्टर-17/18 की पुलिस टीमों द्वारा विशेष कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान तीनों थानों के कुल 13 बीसी (बैड कैरेक्टर) अपराधियों को बुलाया गया। पुलिस टीम द्वारा उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित विवरण की गहनता से जांच एवं समीक्षा की गई। पुलिस टीम द्वारा सभी को उनके आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में अवगत कराते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न होने तथा कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की सख्त हिदायत दी गई। इसके अलावा सभी 13 बीसी को निर्देश दिए गए कि वे प्रत्येक 15 दिन में संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, ताकि उनकी गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जा सके। पुलिस टीम द्वारा सभी को किसी भी अपराध या अपराधी से संबंधित जानकारी भी पुलिस से सांझा करने के संबंध में निर्देश दिए गए। पुलिस उपायुक्त पश्चिम शशि शेखर के मुताबिक,गुरुग्राम पुलिस द्वारा आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की समय-समय पर समीक्षा कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गुरुग्राम: एनसीसी सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, चरित्र निर्माण की पाठशाला- राम नरेश

गुरुग्राम। यहां सेक्टर-10ए स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में शक्ति, देशभक्ति और लीडरशिप का संगम देखने को मिला। यह कार्यक्रम 5-हरियाणा बटालियन एनसीसी गुरुग्राम ने आयोजित किया। इसमें रोहतक ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राम नरेश चीफ गेस्ट के तौर पर और कर्नल समीर कुमार कौशिक विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे। स्कूल के प्रबंधक राजीव कुमार ने बताया कि इस अवसर पर स्कूल में बेहतरीन सजावट की गई।

कार्यक्रम में ब्रिगेडियर राम नरेश द्वारा करियर पर चर्चा और एक देश, एक भावना, एक गर्व दिखाई गई। सत्यमेव जयते लिखा एनसीसी का बैनर देशभक्ति का प्रतीक बन गया। एसडी/एसडब्ल्यू कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान प्रिंसिपल दीपिंदर कौर, डिप्टी प्रिंसिपल डॉ. मोनिका लक्कड़ा, कोऑर्डिनेटर किरण बाला और अनीता वाधवा और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड लक्ष्मण सिंह मौजूद थे। ब्रिगेडियर राम नरेश ने डिसिप्लिन, करेज, लीडरशिप, देशभक्ति और आर्म्ड फोर्सेज में करियर के मौकों के बारे में बात की। कर्नल समीर कुमार कौशिक ने भी अपने विचार रखे। इसके बाद एक डायलॉग सेशन हुआ। ब्रिगेडियर राम नरेश ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की पाठशाला है। यहां कैडेट सबसे पहले डिसिप्लिन सीखता है। समय पर उठना, परेड में एक साथ कदम मिलाना, आदेश का पालन करना और अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना, ये छोटी-छोटी आदतें ही उसे जीवन में बड़ा बनाती हैं। दूसरा बड़ा गुण है करेज यानी साहस।

एनसीसी के कैंप, ट्रैकिंग, फायरिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग कैडेट को डर से लडना सिखाती है। वह कठिन परिस्थिति में भी घबराता नहीं, बल्कि आगे बढ़कर सामना करता है। तीसरा स्तंभ है लीडरशिप। परेड कमांडर बनना हो, कैंप में टीम संभालनी हो या सामाजिक सेवा का अभियान चलाना हो, एनसीसी हर कैडेट को नेतृत्व का मौका देता है। इससे उसमें निर्णय लेने की क्षमता, टीम भावना और दूसरों को साथ लेकर चलने की कला विकसित होती है। विद्यालय के प्रबंधक राजीव कुमार ने कहा कि एनसीसी आर्म्ड फोर्सेज में करियर का भी द्वार खोलती है। एनसीसी युवाओं को अनुशासित, साहसी, देशभक्त और जिम्मेदार लीडर बनाती है।

खोड़ा में लोगों का जीना दुश्वार...सड़कें बदहाल, लोगों को आने जाने में भी हो रही दिक्कत

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

साहिबाबाद। खोड़ा में नगर पालिका परिषद की ओर से कराए जा रहे पेयजल पाइपलाइन डालने के काम से लोगों को परेशानी हो रही है। निवासियों का आरोप है कि कई कॉलोनियों में काम कराने के बाद सड़कों को समतल नहीं किया गया। सड़कें बदहाल हो गई हैं। इससे आवागमन के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है।



स्थानीय निवासी दीपक रावत का कहना है कि लोकप्रिय विहार में पेयजल लाइन डालने के बाद नगर पालिका ने मार्ग को समतल नहीं कराया। यही हाल अन्य कॉलोनियों का भी है। सड़क बदहाल हो गई हैं। मार्ग गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। स्थानीय निवासी मुसैद सैफी का कहना है कि कॉलोनी में पेयजल पाइपलाइन डालने और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम किया गया। काम के बाद कई जगह अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। जहां मलबा पड़ा हुआ है। वहां अब लोग कूड़ा डाल रहे हैं। इससे गंदगी फैल रही है। साथ ही नालियां गंदगी से अट रही हैं। शिकायत के बाद भी मलबा हटाया नहीं जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने समस्या के समाधान की मांग की है। इस बारे में अवर अभियंता अनुज गोयल का कहना है कि कई कालोनियों में सड़क का निर्माण कराया गया है। अभी सड़कों का काम चल रहा है।

गुरुग्राम: कंपनी के क्लाउड सर्वर पर साइबर हमला कर 25.67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

गुरुग्राम,एजेंसी। ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी पे-यू का क्लाउड सर्वर पर साइबर हमला हो गया। इस साइबर हमले के दौरान कंपनी के खाते से 25.67 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई। ठगी की यह रकम ट्रांसफर करने के लिए जिन लोगों ने बैंक खाते उपलब्ध कराए थे, उनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।



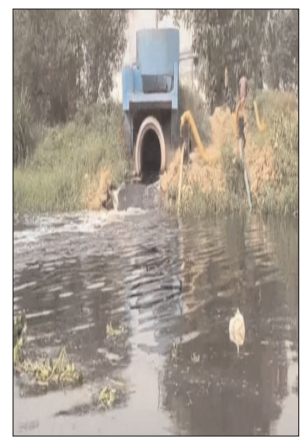
पुलिस के अनुसार नौ नवंबर 2026 को पे-यू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से थाना साइबर अपराध दक्षिण में एक शिकायत दी गई थी। शिकायत में कहा गया कि कंपनी के सर्वर का अनाधिकृत रूप से एक्सेस प्राप्त कर वहां कमांड चलाते हुए नए लाभार्थी खाते रजिस्टर किए गए। कंपनी की जानकारी और अनुमति के बिना उन खातों में लगभग 25.67 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर लिए गए। इस तरह से कंपनी के साथ धोखाधड़ी की गई। इस शिकायत के आधार पर थाना साइबर अपराध दक्षिण में केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने इस मामले में दो आरोपियों को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अतर सिंह व लवप्रीत सिंह निवासी जिला लुधियाना के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि इस ठगी गई राशि में से छह लाख 20 हजार रुपये आरोपी अतर सिंह के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। यह बैंक खाता आरोपी अतर सिंह ने दो प्रतिशत कमीशन पर आरोपी लवप्रीत को उपलब्ध कराया था। आरोपी लवप्रीत सिंह ने यह बैंक खाता दो प्रतिशत कमीशन पर एक अन्य व्यक्ति को बेचा था।

कर्ज से परेशान युवक जहरीला पदार्थ निगल खुद ही अस्पताल पहुंचा

गुरुग्राम। सेक्टर-9 थाना क्षेत्र में कर्ज से परेशान 28 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। गंभीरावस्था में वह खुद ही निजी अस्पताल में पहुंचा। शरीर में जहर फैल जाने के कारण करीब ढाई घंटे बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के जट्टारी गांव का रहने वाला विजयदीप यहां परिवार के साथ बसई में रहता था। विजयदीप ने मंगलवार दोपहर करीब दो बजे बसई से धनकोट फ्लाईओवर पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। जब जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो वह परेशान हो गया और खुद ही एक निजी अस्पताल में पहुंचा। वहां डॉक्टर्स ने उसका उपचार शुरू किया। उपचाराधीन रहने के करीब ढाई घंटे बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विजयदीप शादीशुदा था और उसका तीन साल का एक बेटा भी है। वह एक लैब में निजी नौकरी करता था। उसके जीजा ललित कुमार ने पुलिस को बताया कि विजयदीप कर्ज को लेकर काफी समय से परेशान रहता था।

गाजियाबाद में जमकर उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां, हरनंदी में छोड़ा गया एसटीपी का पानी

साहिबाबाद। पुरबिया जनकल्याण परिषद ने हरनंदी में करहेड़ा-मोरटी में बने एसटीपी का पानी छोड़ने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से शिकायत की है। इसको लेकर तीन दिन पहले त्योहार के दिनों का एक वीडियो भी बनाया गया, जिसमें हरनंदी में पानी गिरता दिख रहा है। परिषद के सदस्यों ने बिना शोधित पानी को हरनंदी में गिरने से रोकने की मांग की है। परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जय दीक्षित ने बताया कि छठ पर गंगनहर से श्रद्धालुओं के लिए गंगाजल हरनंदी में छोड़ा जाता है लेकिन पर्व वाले दिन एसटीपी से भी पानी नदी में छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि वह मौके पर थे और बिना शोधित पानी हरनंदी में छोड़ा गया। उन्होंने इसका वीडियो बनाकर प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की लेकिन पानी को बंद नहीं कराया गया है।



हर घंटे एसटीपी का पानी इसमें छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे श्रद्धालुओं में भी नाराजगी है। इस बारे में जल निगम के अधिशासी अभियंता अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि हरनंदी में नौ नालों का पानी जा रहा है। इनमें से नगर निगम के दो नालों की टेपिंग विभाग करा रहा है। बाकी के लिए नमामि गंगे में डीपीआर गई है। करहेड़ा में सीवर लाइन डालने और कनेक्शन का काम लगभग हो चुका है। यहां 68 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी से पानी शोधित होगा। एसटीपी से किसी तरह का पानी नदी में नहीं छोड़ा जा रहा है।

आईजीएल का बिल जमा कराने के नाम पर साइबर अपराधियों ने छह लाख 80 हजार रुपये ठगे



नोएडा। आईजीएल गैस का बिल जमा करने के नाम पर अज्ञात साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उनके खाते से छह लाख 80 हजार रुपये धोखाधड़ी करके निकाल लिया। पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि बुधवार सुबह सुशील कुमार कुलश्रेष्ठ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह सेक्टर 78 स्थित एक सोसाइटी में रहते हैं। पीड़ित के अनुसार 13 नवंबर दोपहर को उनके पास एक फोन आया। फोन पर कहा गया कि उनका आईजीएल का बिल जमा नहीं हुआ है। उन्होंने समझा कि आईजीएल कंपनी का कर्मचारी बोल रहा है। उसने कहा कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा।

उन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया तथा उससे बात की। उसने एपीके फाइल लोड करवाई। इसी बीच आरोपित ने उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया तथा उनके खाते से विभिन्न बार में छह लाख 80 हजार रुपये निकाल लिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित ने आज सुबह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नोएडा में बाइक सवारों ने चुराईं 6.5 लाख की तीन घोड़ियां

नोएडा। यूपी के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब गरीब परिवारों की रोजी-रोटी भी सुरक्षित नहीं है। नोएडा के गढ़ी चोखण्डी गांव में चोर एक व्यक्ति की साढ़े छह लाख रुपये कीमत की तीन घोड़ी चोरी कर ले गए। पीड़ित ने फेज तीन थाने में मंगलवार को मामला दर्ज कराया है। गढ़ी चोखण्डी के कृष्णा विहार के गली नंबर दो में विकास परिवार संग रहते हैं।

वह घोड़ी से अपना जीवन यापन करते है। वर्तमान में उनके पास तीन घोड़ियां थीं। एक घोड़ी की कीमत तीन लाख रुपये, दूसरी की दो लाख रुपये और तीसरी की कीमत डेढ़ लाख रुपये थी। उनका परिवार रविवार रात को घर में सो रहा था। रात में चोर तीनों घोड़ी चोरी कर ले गए। सुबह जागने पर तीनों घोड़ियां नहीं दिखने पर परिवार घबरा गया। आसपास के लोगों से पूछा। गलियों और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फुटेज चेक की गई। उसमें बाइक सवार तीन संदिग्ध दिखे। तीनों एक-एक कर घोड़ियों को चोरी कर ले जाते दिखे। पीड़ित ने फेज तीन थाना पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अब उनके



बच्चों का पेट कैसे भरेगा और घर का खर्च कैसे चलेगा। मेहनत कर रोजी-रोटी कमाने वाले गरीब परिवारों की संपत्ति भी सुरक्षित नहीं है। परिवार ने नोएडा पुलिस से गुहार लगाई है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितो की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाए और चोरी हुए घोड़े-घोड़ी को बरामद कराए जाए। एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। तीनों घोड़ियों की तलाश में टीम लगी है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर

मृत्युंजय दीक्षित



उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और संगठन बल के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान करने में जुट गई है। भाजपा ने युवा, महिला, किसान व गरीब समाज को साधने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याजनाओं की बहार ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा 'तब और अब' के अंतर को बताते हुए जनता के मध्य उतर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी अब हर उत्सव के दौरान जनमानस को यह बता रहे हैं कि 'उपद्रव से उत्साह की यात्रा नए उप्र की पहचान बन चुकी है।' प्रदेश सरकार वर्तमान समय में जहां अपने संकल्प पत्र को पूर्णता प्रदान करने की ओर अग्रसर है वहीं नये लक्ष्यों का भी संकल्प लिया जा रही है। योगी आदित्यनाथ हिन्दू समाज को एकजुटता प्रदान करने का कोई अवसर नहीं चूक रहे हैं।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल से युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर और हरदोई के 300 से अधिक शिक्षण संस्थानों के 50 हजार से अधिक युवाओं को टैबलेट दिया। मुख्यमंत्री योगी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से अपना नाम मतदाता सूची मे दर्ज करवाने की अपील करते हुए उनसे बजरंग बली की तरह अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी अपनी सरकार में 2019 से अभी तक युवाओं के लिए हुए कार्यों की जानकारी देते हुए अगली सरकार में युवाओं के लिए किए जा रहे संकल्पों की झलक भी दिखाई। योगी ने युवाओं से वादा किया कि आगामी 26 जनवरी तक युवाओं को एक लाख नौकरियां और दी जाएंगी। पहले चरण में अभी तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। इनमें इन्फोसिस के सहयोग से अनेक पाठयक्रमों की डिजिटल सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई है। इनमें योग से लेकर एआई और डीपटेक जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। युवा साथी ऐप के माध्यम से छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम और सीएम इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और पीएम मुद्रा सहित केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती अवसर पर यह योजना प्रारंभ की गई थी और दो करोड़ युवाओं को डिजिटल उपकरण देने का संकल्प लिया गया था। आईआईएम लखनऊ से कराए गए अध्ययन में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश भारत का सबसे युवा प्रदेश है, जहां 56 से 60 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग की है। देश की राजधानी दिल्ली में नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश भारत सरकार ने झेला था तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद त्याग भी करना पड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल-कालेजों की बदहाली के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी युवाओं को भड़काने का असफल प्रयास किया किंतु प्रदेश सरकार की सतर्कता के कारण अराजक तत्व प्रदेश के युवाओ को भड़काने में नाकाम रहे। प्रदेश सरकार युवाओं को यह भी बता रही है कि 2017 से पूर्व प्रदेश में युवाओं के समक्ष पहचान का संकट था जबकि आज वे गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी यह बात भी अवश्य बताते हैं कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अब तक प्रदेश में 9.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आठ हजार लेखपालों और 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी हो चुकी है।सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।अगले दस दिनों में 42 हजार होमगार्डों को भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग, लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी। अभी तक शिक्षा विभाग के 3,568 पंचायती राज विभाग के 1,375 खेल कोटे के 470 फ़ोरेंसिक विभाग के 28, पुलिस के 4,543 उपनिरीक्षकों और राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

प्रदेश के युवाओं को केवल सरकारी नौकरी ही नहीं दी जा रही है अपितु विभिन्न माध्यमों से अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे किंतु आज 25 हजार से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। बदलते यूपी मे आज ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अमेठी में ए के -203 राइफल का निर्माण हो रहा है। देश में बनने वाले 55 प्रतिशत मोबाइल फोन और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट का निर्माण यूपी में हो रहा है। लखनऊ की एचसीएल इकाई में एक समय केवल 100 कर्मचारी थे आज उनकी संख्या 18 हजार है। आज का उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा क्योंकि अब प्रदेश दंगा मुक्त, माफिया मुक्त व अराजकता मुक्त हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाने के कारण अब निवेशक भी प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं जिसके कारण युवाओं को रोजगार व नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए विदेश जाने के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। कौशल विकास के भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आगामी समय में प्रदेश सरकार छात्राओं के कल्याण के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का अभियान प्रारंभ करेगी। वन ब्लॉक व वन पूर्व सैनिक योजना से भी युवाओं को प्रशिक्षण देने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक पूर्व सैनिक को जिम्मेदारी देकर स्थानीय युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अग्निवीर भर्ती की तैयारियों के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रदेश सरकार चुनावों की घोषणा के पूर्व अभी अपने तरकश से कुछ और तीर निकाल सकती है। इनमें महिलाओं के कल्याण के लिए भी बड़ी योजना आने की सम्भावना है। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार अपने मतदाता को बांध कर रखने के लिए कल्याण योजनाओं को अधिकतम विस्तार देने का प्रयास करेगी।

1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया किन्तु 1960 में फिरोज गांधी का अकस्मात् निधन हो गया। पिता जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी इंदिरा के कंधों पर आई तो अपनी दृढ़ता, दबंगता, निडरता और वाकपटुता से उन्होंने दुनियाभर को अपना लोहा मानने को विवश कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित एवं प्रभावशाली देशों में भी उनकी तूती बोलती थी। 1966 से 1977 तक उन्होंने देश पर एकछत्र शासन किया और उनकी कार्यशैली तथा देश के प्रति उनका समर्पण भाव देखकर विरोधी भी उनकी सराहना किए बिना नहीं रह पाते थे। हालांकि लालबहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा को शुरूआती दौर में 'गूंगी गुड़िया' की उपाधि दी गई थी किन्तु बहुत ही कम समय में अपने साहसिक निर्णयों से इंदिरा ने साबित कर दिखाया था कि वो एक 'गूंगी गुड़िया' नहीं बल्कि 'लौह महिला' हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की शानदार जीत के बाद इंदिरा जी जनमानस की आंखों का तारा बन गई थी किन्तु 1975-77 के आपातकाल ने उनकी छवि पर ग्रहण लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और उस दौर ने उनकी छवि एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर दी। यही वजह रही कि 1977 में इंदिरा को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और सत्ता उनके हाथ से छिन गई किन्तु निराश होना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था, इसलिए 1980 में एक बार फिर विशाल बहुमत के साथ वह सत्ता में लौटी।

विश्व राजनीति में भारत की बुलंद आवाज थी इंदिरा गांधी

योगेश कुमार गोयल



पं. जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवम्बर 1917 को जब प्रियदर्शिनी नामक कन्या ने जन्म लिया था तो किसे पता था कि यही कन्या आगे चलकर न केवल इस देश की बागडोर संभालेगी बल्कि अपनी दबंगता से पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। ऑक्सफोर्ड और स्विट्जरलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् इंदिरा गांधी ने उच्च पद पर नौकरी करने या कोई अन्य कार्य करने के बजाय अपना जीवन देशसेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। देशभक्ति की भावना इंदिरा जी में बचपन से ही कूट-कूटकर भरी थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आव्हान से प्रेरित होकर बचपन में ही इन्होंने अपने घर के बाहर अपने कीमती कपड़ों की होली जलाकर न केवल अपनी इसी भावना का परिचय दिया था बल्कि उसके बाद इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर इस आन्दोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ा था। इंदिरा जी के स्कूली दिनों में एक दिन स्कूल में गांधी जी के आमरण अनशन को लेकर एक सभा का आयोजन था, जिसमें बच्चों को भी बोलने का अवसर दिया गया था। जब इंदिरा जी ने बोलना शुरू किया तो सभागार में सन्नाटा छा गया और सभी एकटक इंदिरा को निहारने लगे कि इतनी छोटी बालिका इतनी गूढ़ बातें कैसे कर रही है। उन्होंने कहा, ''आखिर स्वर्ण अपने ही दलित भाईयों को गिरा हुआ, छूत और निकृष्ट क्यों समझते हैं तथा उनके साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार क्यों करते हैं? अगर हमने अपनी ही सेवा करने वालों का इस तरह से निरन्तर तिरस्कार न किया होता तो आज अंग्रेजों को इस प्रकार लाभ उठाने का अवसर न मिल रहा होता और न ही बापू को इस तरह से आमरण अनशन कर अपने प्राण दांव पर लगाने पड़ते।'' इंदिरा जी की इन गूढ़ और तर्कसम्मत बातों के समक्ष सभी नतमस्तक थे और उनकी सराहना कर रहे थे। इंदिरा में बचपन से ही एक अच्छी राजनेता होने के तमाम गुण विद्यमान थे। 21 वर्ष की आयु में वह कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कूद पड़ी। उसके बाद उन्होंने आजादी के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया किन्तु 1960 में फिरोज गांधी का अकस्मात् निधन हो गया। पिता जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी इंदिरा के कंधों पर आई तो अपनी दृढ़ता, दबंगता, निडरता और वाकपटुता से उन्होंने दुनियाभर को अपना लोहा मानने को विवश कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित एवं प्रभावशाली देशों में भी उनकी तूती बोलती थी। 1966 से 1977 तक उन्होंने देश पर एकछत्र शासन किया और उनकी कार्यशैली तथा देश के प्रति उनका समर्पण भाव देखकर विरोधी भी उनकी सराहना किए बिना नहीं रह पाते थे। हालांकि लालबहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा को शुरूआती दौर में 'गूंगी गुड़िया' की उपाधि दी गई थी किन्तु बहुत ही कम समय में अपने साहसिक निर्णयों से इंदिरा ने साबित कर दिखाया था कि वो एक 'गूंगी गुड़िया' नहीं बल्कि 'लौह महिला' हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की शानदार जीत के बाद इंदिरा जी जनमानस की आंखों का तारा बन गई थी किन्तु 1975-77 के आपातकाल ने उनकी छवि पर ग्रहण लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और उस दौर ने उनकी छवि एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर दी। यही वजह रही कि 1977 में इंदिरा को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और सत्ता उनके हाथ से छिन गई किन्तु निराश होना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था, इसलिए 1980 में एक बार फिर विशाल बहुमत के साथ वह सत्ता में लौटी। अपने शासनकाल में उन्होंने कभी अलगाववादी व साम्प्रदायिक आग भड़काने वाले तत्वों को नहीं पनपने दिया। ऐसे तत्वों को उन्होंने बेदर्दी से कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाई।

1980 में पुन: देश का शासन संभालने के बाद पंजाब में अलगाववादी ताकतों ने खालिस्तान की मांग शुरू की और दूसरे देशों की शह पर अपने नापाक इरादों को सफल बनाने के लिए सिख अलगाववादियों ने भयानक नरसंहार का दौर शुरू किया तथा पंजाब में अवैध रूप से हथियारों के जखीरे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। देश की जांबाज, निडर एवं साहसी नेता इंदिरा को भला यह कैसे सहन होता, इसलिए जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सिख अलगाववादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसी पाक जगह में भी हथियारों का विशाल जखीरा इकट्ठा किया है तो उन्हें देश की एकता और अखंडता कायम रखने तथा अलगाववादियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इस पवित्र धर्मस्थल के भीतर न चाहते हुए भी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के तहत पुलिस भेजने का सख्त निर्णय लेना पड़ा। हालांकि उस वक्त स्वर्ण मंदिर के भीतर पुलिस बल भेजने के उनके फैसले की बहुत आलोचना हुई किन्तु जब स्वर्ण मंदिर से हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ और धार्मिक स्थल की आड़ में चल रही इस राष्ट्र विरोधी साजिश का भंडाफोड़ हुआ तो उन्हीं लोगों ने इंदिरा जी की सराहना भी की। उसके बाद इंदिरा ने जिस दिलेरी और दृढ़ता के साथ अलगाववादियों को रौंदा, वह एक मिसाल बन गया लेकिन अलगाववादियों के विरूद्ध चलाए गए उनके इसी ऑपरेशन की वजह से ही वह उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई, जिन्होंने हर हाल में उनकी हत्या कर उन्हें अपने मार्ग से हटाने की ठान ली। इंदिरा जी को स्वयं अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था लेकिन फिर भी वह अपने दृढ़ इरादों से टस से मस न हुई और अलगाववादियों के खिलाफ अपना अभियान पहले से भी तेज कर दिया। 30 अक्तूबर 1984 को भुवनेश्वर की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इंदिरा ने अपनी हत्या का पूर्वाभास होने का स्पष्ट संकेत देते हुए कहा था, ''देश की सेवा करते हुए यदि मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गर्व होगा। मुझे भरोसा है कि मेरे खून की एक-एक बूंद देश के विकास में योगदान देगी और देश को मजबूत एवं गतिशील बनाएगी।' इंदिरा जी के इस भाषण के चंद घंटों बाद ही 31 अक्तूबर 1984 की सुबह करीब सवा नौ बजे उनके दो निजी अंगरक्षकों ने ही उन्हें उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया, जब वह अपने आवास से निकलकर विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देने जा रही थी। उस हत्याकांड से जहां पूरे देश में शोक की लहर छा गई, वहीं दूसरी ओर इंदिरा जी का शहीदी रक्त रंग लाया और इस नृशंस हत्याकांड के बाद सिख अलगाववादियों को मदद मिलनी बंद हो गई तथा इंदिरा जी की शहादत के साथ ही खालिस्तान की मांग भी गहरे दफन हो गई। इंदिरा जी अक्सर कहा करती थी कि उन कायरों और बुजदिलों पर मातम करो, जो दुनिया के जुल्मों से घबराकर इस तरह आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो।

विचार

केंद्र की यह एक सार्थक पहल है: छावनियों में बुजुर्गों और बच्चों की व्यवस्था

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

किसी परिवार की वास्तविक खुशी तब पूरी होती है, जब घर के बुजुर्गों को अपनों का साथ मिले और बच्चों का बचपन सुरक्षित हाथों में हो। आज की व्यस्त जीवनशैली में इन दोनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना अनेक परिवारों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सैन्य छावनियों में बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह और बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर स्थापित करने तथा मौजूदा सुविधाओं के विस्तार का जो निर्णय लिया है, वह संवेदनशील सामाजिक सोच का परिचायक है। वस्तुत: यह पहल अपने भीतर परिवार की तीन पीढ़ियों की चिंता समेटे हुए है। एक ओर कामकाजी माता-पिता को बच्चों की सुरक्षित देखभाल का भरोसा मिलेगा, दूसरी ओर बुजुर्गों को जीवन के इस पड़ाव पर साथ, सम्मान और अपनत्व का वातावरण उपलब्ध होगा। रक्षा प्रतिष्ठानों की व्यवस्थाओं को सामाजिक कल्याण से जोड़ने वाला यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है। इस संबंध में कहना होगा कि भारतीय परिवार व्यवस्था में बुजुर्गों का अनुभव और बच्चों का भविष्य, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों का विस्तार हुआ है। पति-पत्नी दोनों के रोजगार से जुड़े होने के कारण बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय निकालना कठिन होता जा रहा है। दूसरी ओर, उम्रदराज माता-पिता को स्वास्थ्य संबंधी सहयोग, नियमित देखभाल और भावनात्मक संबल की आवश्यकता होती है। रोजगार, स्थानांतरण और व्यस्त दिनचर्या के बीच परिवारों के सामने इन जिम्मेदारियों को निभाने की चुनौती बढ़ी है। सैन्य परिवारों की परिस्थितियां इससे कुछ अधिक जटिल होती हैं। सेना के अधिकारियों और जवानों की तैनाती तथा स्थानांतरण के कारण परिवारों को बार-बार नई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है। ऐसे में छावनियों के भीतर बच्चों और बुजुर्गों के लिए संस्थागत सुविधाओं का विकास एक व्यावहारिक समाधान बन सकता है। इस दिशा में रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत हुआ समझौता महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से इस पहल को प्रशासनिक और वित्तीय आधार मिला है। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। छावनी बोर्डों के अपने बजट से संचालित मौजूदा डे-केयर सेंटरों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन एवं रखरखाव में भी सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही नए केंद्र स्थापित करने और वर्तमान सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। इससे छावनी बोर्डों की प्रशासनिक क्षमता और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

बच्चों के लिए डे-केयर सेंटरों की व्यवस्था आज के कामकाजी परिवारों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। माता-पिता जब अपने कार्यस्थल पर होते हैं, तब बच्चों की सुरक्षा, खानपान और दिनचर्या को लेकर उनकी चिंता स्वाभाविक है। छावनियों में विकसित होने वाले ये केंद्र बच्चों को सुरक्षित वातावरण, नियमित देखभाल, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरे बच्चों के साथ संवाद और सामूहिक गतिविधियां उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में भी सहायक होंगी। इससे माता-पिता को मानसिक राहत मिलेगी और वे अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों पर बेहतर ढंग से ध्यान दे सकेंगे। सैन्य परिवारों के लिए यह सुविधा विशेष उपयोगी होगी, जहां सेवा संबंधी दायित्वों के कारण पारिवारिक दिनचर्या प्रभावित होती रहती है। इस पहल का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृहों की व्यवस्था है। उम्र के साथ व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त संवाद, सामाजिक मेलजोल और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता बढ़ती है। जीवनभर परिवार और समाज के लिए योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के उत्तरार्ध में सम्मान और अपनत्व मिलना चाहिए। ऐसे केंद्रों में उन्हें समान आयु वर्ग के लोगों के साथ समय बिताने, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने और आवश्यक देखभाल प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। यहां यह भी समझना जरूरी है कि बुजुर्गों की जरूरतें दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित नहीं होतीं। उनकी बात सुनने वाला कोई हो, उनके अनुभवों को महत्व मिले और आसपास अपनेपन का वातावरण हो, यह भी उनके सुखी जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। इन गृहों का संचालन इस भावना के साथ होना चाहिए कि वे परिवारों के सहयोगी बनें और बुजुर्गों के पारिवारिक संबंध निरंतर मजबूत रहें।

एक नजर

बिहार प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री बक्सर ताप बिजली घर की दूसरी इकाई का करेंगे उद्घाटन

पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को अपने बिहार प्रवास के दौरान वैशाली जिले में आयोजित एक कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बक्सर जिले के चौसा स्थित 1,320 मेगावाट (660-660 मेगावाट की दो इकाई) क्षमता वाले बक्सर ताप बिजली घर की दूसरी इकाई का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उपरोक्त जानकारी बिहार सरकार के सूचना विभाग द्वारा दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस इकाई से बीते सितंबर में व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। पहली इकाई ने नवंबर 2025 में परिचालन शुरू किया था। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 22 अगस्त 2025 को बोधगया में एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। साल 2014 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार बनने और बक्सर से भाजपा सांसद (बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री) अश्विनी कुमार चौबे के चुने जाने के बाद परियोजना को प्रशासनिक व राजनीतिक गति मिली। विद्युत और कोयला मंत्रालय के हस्तक्षेप से स्थायी कोयला लिंकेज मिला। 7 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 10,439.09 करोड़ रुपये की लागत से इसके निर्माण को मंजूरी दी और 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया।

सदर बाजार में जाम का झाम, ठेले वालों के अतिक्रमण से राहगीर परेशान

सुपौल,एजेंसी। शहर के सदर बाजार में जाम की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। खासकर शाम के समय बाजार में वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ ही सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सड़क किनारे ठेले और अस्थायी दुकानें लगाए जाने से सड़क की चौड़ाई सिमटकर रह गई है। इसके कारण आम राहगीरों से लेकर बाजार में खरीदारी करने पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है।सदर बाजार की मुख्य सड़कों के किनारे जगह-जगह फल, सब्जी और अन्य सामानों के ठेले लगाए जाते हैं। इससे सड़क का काफी हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में आ जाता है। वहीं, शाम के समय खरीदारी करने वालों की भीड़ और वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम की समस्या और विकराल हो जाती है। ई-रिक्शा, सिटी रिक्शा, बाइक और चारपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। लोगों को थोड़ी दूरी तय करने में भी काफी समय बर्बाद करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाता है। इस दौरान सड़क किनारे लगे ठेले और अन्य अस्थायी अतिक्रमण हटाए भी जाते हैं, लेकिन कार्रवाई का असर कुछ दिनों तक ही रहता है। अभियान समाप्त होते ही फिर से सड़क किनारे ठेले और दुकानें सजने लगती हैं। नतीजतन, बाजार की स्थिति दोबारा पहले जैसी हो जाती है। लोगों का कहना है कि केवल अभियान चलाने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए नियमित निगरानी और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जरूरी है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी मनोहर कुमार साहू ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी और जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक सदर बाजार के लोगों को जाम की इस समस्या से जूझना पड़ेगा? स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद से अतिक्रमण पर स्थायी रोक लगाने, ठेला-खोमचा संचालकों के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने तथा बाजार में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार प्रशासन की कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि सदर बाजार को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ठोस और स्थायी व्यवस्था की जाएगी।

छठ पूजा के बाद बढ़ी ठंड, सुबह-शाम कुहासे से जनजीवन प्रभावित

सुपौल। जिले में छठ पूजा के बाद मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में सुबह और शाम ठंड बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि छठ पूजा के बाद से ठंड में अचानक इजाफा महसूस हो रहा है। सुबह के समय सड़कों और खुले इलाकों में कुहासा छाने लगा है, जबकि शाम होते ही ठंडी हवा चलने से ठिठुरन बढ़ जाती है। बढ़ती ठंड के कारण लोग अब गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। सुबह टहलने निकलने वाले लोग जैकेट, स्वेटर और मफलर पहने नजर आ रहे हैं। वहीं बुजुर्ग और बच्चे ठंड से बचने के लिए सुबह देर से घर से निकल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा लेने लगे हैं। ठंड बढ़ने के साथ बाजार में गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ने लगी है। स्वेटर, जैकेट, टोपी और मफलर की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। सुबह के समय कुहासा रहने से सड़कों पर वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। मौसम में बदलाव का असर दैनिक जीवन के साथ खेती-किसानी पर भी दिखने लगा है। किसानों के अनुसार सुबह खेतों में ओस और ठंड बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर ठंड का असर बढ़ने की संभावना है।

पंचकोशी मेला से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे विधायक आनंद मिश्रा

बक्सर। आगामी पंचकोशी मेला को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को विधायक आनंद मिश्रा ने प्रशासनिक एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के विभिन्न तीर्थ स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत प्रणव चटर्जी महाविद्यालय (पीसी कॉलेज) से हुई। इसके बाद पांडेयपट्टी रेलवे गुमटी से पीसी कॉलेज तक रिहायशी मकानों के ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के बिजली तारों का जायजा लिया गया। विधायक ने इस गंभीर विषय पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद अहिरौली स्थित अहिल्या धाम मंदिर, चरित्रवन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, बड़का नुआंव स्थित अंजनी सरोवर समेत पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के अन्य प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया गया। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेला शुरू होने से पहले स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा, यातायात, प्रकाश व्यवस्था तथा परिक्रमा मार्गों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय सीमा में तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, बीडीओ, सिविल सर्जन, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, डीएसपी मुख्यालय एवं औद्योगिक थाना प्रभारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि पंचकोशी मेला बक्सर की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है।

प्रधानमंत्री के प्रस्तावित वैशाली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट ने तैयारियों का लिया जायजा

पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को वैशाली जिले में कच्ची दरगाह-राजापाकर-बिदुपुर छह लेन पुल (नीतीश सेतु) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने राघोपुर के रुस्तमपुर में नवनिर्मित हेलीपैड का निरीक्षण किया। साथ ही पुल के पिलर संख्या 23 और 24 के बीच बनाए जा रहे प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।

निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आएंगे और कच्ची दरगाह-राजापाकर-बिदुपुर छह लेन पुल को जनता को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राघोपुर सहित पूरे बिहार की जनता उनके स्वागत के लिए उत्साहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इलाका लंबे समय तक विकास से अछूता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया। कच्ची दरगाह-राजापाकर-बिदुपुर छह लेन पुल की डीपीआर वर्ष 2012 में तैयार की गई थी और वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके निर्माण कार्य की शुरुआत कराई थी। वर्ष 2026 में पुल का निर्माण पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने इस पूरे इलाके की स्थिति को समझते हुए अभियान चलाकर पुल निर्माण की पहल की



थी। उनके आग्रह पर नीतीश कुमार ने सुल्तानगंज-अगवानी पुल को वर्ष 2013 में स्वीकृति दी थी। वर्ष 2010 में इस इलाके में आयोजित चुनावी सभा के दौरान उन्होंने जनता से यहां पुल बनवाने का वादा किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी और गर्व है कि छह लेन पुल का नामकरण 'नीतीश सेतु' के रूप में किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री राजापाकर स्थित बनारसी चौक और जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र (जाफरपट्टी) पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम स्थल के समीप प्रधानमंत्री के वैशाली आगमन और प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई। बैठक में वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से 21 नवंबर के कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम, कार्यक्रम स्थल के मानचित्र, हेलीपैड, विभिन्न प्रकार के वाहनों की पार्किंग, प्रवेश द्वार, यातायात प्रबंधन और आम लोगों के सुगम आवागमन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम को लेकर अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभा स्थल तक लोगों का आवागमन सुगम और व्यवस्थित रखने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वाहनों का परिचालन भी सुचारू रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, किसान कमलेश यादव की मौत, दो महिलाओं समेत पांच घायल

नवादा,एजेंसी। जिले में रोह थाना क्षेत्र के भंडाजोर और गुड़िहारी गांव के लोगों के बीच गुरुवार को भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। खेत में धान की कटाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में गुड़िहारी गांव निवासी किसान कमलेश यादव की मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

घटना के संबंध में घायल अखिलेश यादव ने बताया कि उनके परिवार ने भंडाजोर गांव के मांझी परिवार से 27 कट्ठा जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर उनका परिवार वर्ष 2021 से ही खेती-बारी करता आ रहा है। गुरुवार को परिवार के सभी सदस्य खेत में धान की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान भंडाजोर गांव के संतोष सिंह, चुहन सिंह, कार्यानंद सिंह और निशांत सिंह समेत 15 से 20 लोग हथियारों से लैस होकर खेत पर पहुंच गए। आरोप है कि वहां पहुंचते ही उन लोगों ने धान काट रहे परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान हुई मारपीट में बूंदी यादव के पुत्र कमलेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, बूंदी यादव की पत्नी जयमंती देवी, पुत्र अखिलेश यादव, सत्येंद्र यादव और पिंकी कुमारी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान कमलेश यादव की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज जारी है। घायल पक्ष का कहना है कि विवादित जमीन पर उनका वर्ष 2021 से ही कब्जा है और वे लगातार उस पर खेती करते आ रहे हैं। इसके बावजूद दूसरे पक्ष के लोग जमीन पर अपना दावा पेश कर रहे थे। गुरुवार को धान की कटाई के दौरान इसी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं, मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसा लेकर उपद्रवियों को मदद और संरक्षण दिया जा रहा था। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, पुलिस पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

खेल से संभव है जीवन का चौमुखी विकास : डॉ अनुज कुमार

नवादा। खेल के माध्यम से जीवन का चौमुखी विकास संभव है। खेल न केवल शारीरिक और मानसिक क्षमता को मजबूत करता है, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और टीम भावना जैसे गुणों का भी विकास करता है। उक्त बातें मॉडर्न शैक्षणिक समूह के निदेशक डॉ. अनुज कुमार ने बुधवार को मॉडर्न क्रिकेट सीनियर लीग 2026-27 के उद्घाटन समारोह में कहीं। उन्होंने फीता काटकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। मॉडर्न शैक्षणिक समूह के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में समूह के पांच विद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए डॉ. अनुज कुमार ने कहा कि खेल में जीत और हार से अधिक महत्वपूर्ण अनुशासन, समर्पण और खेल भावना है। प्रत्येक खिलाड़ी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों से अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवादा और बिहार का नाम रोशन करने का आह्वान किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल, हिसुआ और मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, न्यू एरिया के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यू एरिया की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में नौ विकेट पर 79 रन बनाए। अनिकेत ने 16, कन्हैया ने 14 और अमन ने 12 रन बनाए। हिसुआ की ओर से कप्तान अभिषेक शर्मा ने तीन, जबकि उमंग और कन्हैया ने दो-दो विकेट हासिल किए। जवाब में हिसुआ की टीम ने कप्तान अभिषेक शर्मा के नाबाद 46, हिमांशु के नाबाद 13 और सत्यम के 10 रनों की बदौलत दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

दिन के दूसरे मुकाबले में मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, कुंती नगर ने मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल, नारदीगंज को 48 रनों से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कुंती नगर ने रेहान मलिक के 26, आदित्य राज के 16 और आयुष मोहन के 10 रनों की मदद से 96 रन बनाए। जवाब में नारदीगंज की पूरी टीम 48 रनों पर सिमट गई। कुंती नगर के शिवम और कृष्ण ने चार-चार विकेट चटकाए। शिवम को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पूरी प्रतियोगिता का संचालन पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी एवं बिहार स्टेट पैनल अंपायर राकेश रंजन की देखरेख में किया जा रहा है।

सोनपुर मेला 2026 की युद्ध स्तर पर चल रही तैयारी जिलाधिकारी और एसएसपी ने की समीक्षा

सारण,एजेंसी। विश्वप्रसिद्ध हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर मेला-2026 के सफल, सुव्यवस्थित और आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। मेले की तैयारियों को युद्ध स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में अनुमंडल सभागार सोनपुर में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेला क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, और सांस्कृतिक आयोजनों समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र की लाइटिंग और प्रकाश व्यवस्था की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि आवागमन मार्ग पर पर्याप्त और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मेला क्षेत्र की सभी स्ट्रीट लाइटों की समय रहते जांच और आवश्यक मरम्मत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पंडालों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी पंडालों का निर्माण पूरा होने के बाद अग्निशमन, भवन निर्माण और विद्युत विभाग से विधिवत जांच कराकर सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।

मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग स्थलों, बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट की व्यवस्था की समीक्षा की गई। यातायात प्रबंधन को इस तरह



लागू करने पर जोर दिया गया जिससे पर्यटकों को आवागमन में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं स्वच्छता और पेयजल के मोर्चे पर नगर परिषद को पर्याप्त संख्या में शौचालय और यूरिनल बनाने, उनकी नियमित साफ-सफाई रखने तथा वाटर स्टैंड पोस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन की ओर से एक बेहतरीन पहल करते हुए सभी शौचालयों, यूरिनल्स और पेयजल स्टैंड पोस्ट की गूगल लोकेशन तैयार कर साझा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि आगंतुकों को इन सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिल सके। मेले के फूड कोर्ट को लेकर एक खास निर्देश जारी किया गया है। डीएम ने कहा कि सोनपुर मेला के फूड कोर्ट में बिहार के सभी जिलों के विशिष्ट और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएं। इसके लिए विभिन्न जिलों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को एक ही स्थान पर बिहार के पारंपरिक खानपान की विविधता का अनूठा अनुभव मिल सके। बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, निर्धारित तिथियों पर होने वाली गंगा आरती और वर्चुअल 3ष्ठ प्रदर्शन की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा, एशिया के सबसे बड़े पशु मेला की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी को पर्याप्त मोबाइल वेटरनरी यूनिट तैनात करने और पशुओं के स्वास्थ्य उपचार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राजीव रंजन प्रसाद को जदयू में राष्ट्रीय महासचिव, मीडिया प्रभारी सह राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी, जीकेसी सुपौल ने दी बधाई

सुपौल,एजेंसी। जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता एवं ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस (जीकेसी) के ग्लोबल अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने पर सुपौल में हर्ष का माहौल है। इस अवसर पर ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की जिला इकाई की ओर से बधाई सभा आयोजित कर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। सभा में जीकेसी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उनके मनोनयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे संगठन के लिए गौरव का विषय बताया। जीकेसी के जिलाध्यक्ष रुद्र प्रताप लाल ने कहा कि राजीव रंजन प्रसाद को मिली नई जिम्मेदारी उनके लंबे राजनीतिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और संगठन के प्रति समर्पण का परिणाम है। उनकी वक्तृत्व क्षमता, वैचारिक स्पष्टता और राजनीतिक अनुभव से पार्टी के संगठनात्मक एवं मीडिया संबंधी कार्यों को नई दिशा मिलेगी।

युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार मल्लिक ने कहा कि राजीव रंजन प्रसाद की राजनीतिक यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने हमेशा युवाओं की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को महत्व दिया है। उनके मार्गदर्शन से युवा पीढ़ी को सकारात्मक दिशा मिलेगी। महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष नीता कुमारी ने कहा कि राजीव रंजन प्रसाद सामाजिक समरसता और महिला सशक्तीकरण के पक्षधर रहे हैं। नई



जिम्मेदारी मिलने से संगठन में महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी को और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। विधिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता शशांक राज श्रीवास्तव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैचारिक स्पष्टता, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और प्रभावी संवाद की अहम भूमिका होती है। राजीव रंजन प्रसाद की संगठनात्मक दक्षता एवं तार्किक अभिव्यक्ति पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने में उपयोगी होगी। चिकित्सक प्रकोष्ठ के डॉ. सत्यप्रकाश मल्लिक ने कहा कि राजीव रंजन प्रसाद का सामाजिक दृष्टिकोण व्यापक रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता सराहनीय है। उन्हें मिली नई जिम्मेदारी का लाभ पार्टी और समाज दोनों को मिलेगा। सभा में उपस्थित अन्य सदस्यों ने भी उनके मनोनयन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे संगठन के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है।

बेतिया में सेनको गोल्ड शोरूम से दिनदहाड़े 30-40 करोड़ के आभूषणों की लूट

बेतिया,एजेंसी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में बुधवार को हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी। कालीबाग थाना क्षेत्र के सुप्रिया रोड स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम में तीन बाइक से पहुंचे आठ अपराधियों ने हथियार के बल पर कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। इसके बाद शोरूम में रखे सोने और हीरे के आभूषण बैग में भरकर फरार हो गए। शोरूम मालिक के अनुसार, लूटे गए आभूषणों की अनुमानित कीमत 30 से 40 करोड़ रुपये है। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई है। ज्वेलरी कारोबारियों में भी दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी हरकिशोर राय, एसएसपी कुमार गौतम और सदर वन एसडीपीओ अजीत कुमार करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम को भी बुलाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार दोपहर तीन बाइक पर सवार होकर आठ अपराधी शोरूम पहुंचे। इनमें दो बाइक पर तीन-तीन और तीसरी बाइक पर दो अपराधी सवार थे। सभी हथियारों से लैस थे। शोरूम में प्रवेश करते ही उन्होंने कर्मचारियों को हथियार के बल पर कब्जे में ले लिया। अपराधियों ने कर्मचारियों के हाथ बांध दिए और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद शोरूम में रखे सोने और हीरे के आभूषण बैग में भरने लगे। इस दौरान अपराधियों ने शोरूम के सुरक्षा गार्ड मन्नू चौबे के सिर पर प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया। वहीं, शोरूम में मौजूद दो ग्राहकों के मोबाइल फोन फर्श पर पटककर तोड़ दिए। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरों और काउंटर में भी तोड़फोड़ की। करीब 20 मिनट तक लूटपाट करने के बाद सभी आभूषण लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि व्यस्त सुप्रिया रोड पर स्थित शोरूम में करीब 20 मिनट तक अपराधी लूटपाट करते रहे, लेकिन आसपास के दुकानदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी। अपराधियों के भागने के बाद शोरूम कर्मचारियों ने शोर मचाया, तब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई। घटना के समय शोरूम में करीब सात से आठ कर्मचारी और दो-तीन ग्राहक मौजूद थे। कर्मचारियों में चार से पांच महिलाएं भी शामिल थीं। अपराधियों ने सभी को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की। घटना के बाद कर्मचारियों में भय और दहशत का माहौल है। घायल सुरक्षा गार्ड को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी हरकिशोर राय और एसएसपी कुमार गौतम ने शोरूम में करीब तीन घंटे तक जांच की। इस दौरान कर्मचारियों से अलग-अलग पूछताछ की गई। एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। पुलिस शोरूम और आसपास के प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

एक नजर

न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में धीमी ओवर गति पर भारत को जुर्माना, मैच फीस का 35 प्रतिशत कटा

नई दिल्ली,एजेंसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम वनडे मुकाबले में धीमी ओवर गति से गेंदबाजी करने के कारण भारतीय टीम पर मैच फीस का 35 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेले गए मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली भारतीय टीम निर्धारित समय में अपने लक्ष्य से सात ओवर पीछे रह गई थी। समय की छूट को शामिल करने के बाद मैच रेफरी रंजन मदुगले ने टीम पर यह जुर्माना लगाया। आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत निर्धारित समय में ओवर पूरे नहीं करने पर खिलाड़ियों पर प्रत्येक ओवर के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, कुल जुर्माना मैच फीस के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। भारत के सात ओवर पीछे रहने के कारण प्रत्येक खिलाड़ी की मैच फीस से 35 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। नियमित वनडे कप्तान शुभमन गिल की अनुपस्थिति में अंतिम दो मुकाबलों में टीम की कमान संभालने वाले अय्यर ने गलती स्वीकार कर ली और मैच रेफरी की ओर से प्रस्तावित सजा मान ली। आईसीसी के अनुसार, अय्यर के अपराध स्वीकार करने के कारण औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। भारतीय टीम पर आरोप मैदानी अंपायर पॉल रीफेल और वेन नाइट्स के अलावा तीसरे अंपायर कुमार धर्मसेना तथा चौथे अंपायर क्रिस ब्राउन ने लगाया था। इस जुर्माने से पहले भारत ने पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर चार मैचों की श्रृंखला 3-1 से अपने नाम की थी।

घुटने की सर्जरी के चलते दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर हुए जैकब बेथेल, आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे



नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल घुटने की चोट के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। उन्हें अपने दाएं घुटने की सर्जरी करानी होगी। इस वजह से वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी व्हाइट बॉल सीरीज के साथ-साथ दिसंबर में होने वाले दक्षिण अफ्रीका दौरे से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन में भी नहीं खेल पाएंगे। आईसीसी वेबसाइट के मुताबिक बेथेल 2026 में ज्यादातर समय घुटने की समस्या से जूझते रहे हैं। उन्होंने जुलाई में भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में वनडे मुकाबले में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। इस मैच में उन्होंने 91 रन की पारी खेली थी। इसके बाद से वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेले हैं। 23 वर्षीय बेथेल को ऑस्ट्रेलिया में जारी व्हाइट बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम से जुड़ना था। इसके बाद उन्हें दिसंबर में होने वाले दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी जाना था। हालांकि, घुटने की चोट दोबारा उभरने के कारण उन्हें दोनों सीरीज से बाहर होना पड़ा है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जैकब बेथेल के दाहिने घुटने की इस हफ्ते सर्जरी होगी और उन्हें दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर कर दिया गया है। अब यह देखना होगा कि बेथेल फरवरी में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज और मार्च में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले एकमात्र डे-नाइट टेस्ट तक फिट हो पाते हैं या नहीं। इंग्लैंड को इसके बाद 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज और आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेना है। ऐसे में बेथेल की फिटनेस टीम के लिए अहम होगी। घुटने की चोट के कारण बेथेल आईपीएल 2027 में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने उन्हें टीम से रिलीज किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि जैकब बेथेल को रिलीज करना हमारे लिए बेहद मुश्किल फैसला था। हमने यह निर्णय बहुत भारी मन से लिया है। दुर्भाग्य से उनके घुटने की चोट दोबारा उभर आई है। फिलहाल उनकी वापसी, चोट से उबरने और रिहैबिलिटेशन की समय-सीमा को लेकर काफी अनिश्चितता है।

'हम अपना खेल खेलना चाहते हैं', एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सलीमा टेटे ने बताई टीम की रणनीति

भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की शुरुआत से पहले भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने साफ कर दिया है कि टीम का पूरा ध्यान विरोधियों की रणनीति पर नहीं बल्कि अपने खेल और प्रदर्शन पर रहेगा। सलीमा के मुताबिक, टीम कोच के निर्देशों और अपने गेम प्लान के अनुसार मैदान पर उतरेगी। 19 से 28 नवंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में मैजूदा चैंपियन भारत का सामना चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड से होगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। राउंड-रॉबिन चरण के अंत में शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 19 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ करेंगे। इसके बाद 21 नवंबर को दक्षिण कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड और 24 नवंबर को चीन से और 25 नवंबर को जापान के खिलाफ मैच होगा। सेमीफाइनल 27 नवंबर को और मेडल मैच 28 नवंबर को खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले हॉकी इंडिया की ओर से जारी बयान में भारतीय कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं। हम बस खुद पर, टीम की संरचना पर और कोच के निर्देशों का पालन करने पर ध्यान दे रहे हैं। संक्षेप में कहें तो, हम अपना खेल खेलना चाहते हैं। मुख्य कोच सजोर्ड मारिन ने कहा कि हम चाहते हैं कि खिलाड़ी अलग-अलग पोजिशन पर खेल सकें। इससे टीम की गहराई बढ़ती है और अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो यह बहुत मददगार साबित होता है, खासकर ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में। साथ ही, यह खिलाड़ियों के विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि हम यह देखना चाहते हैं कि क्या इससे हमारे खेलने के तरीके में कुछ नया जुड़ता है और क्या इससे टीम में वे सुधार आते हैं जो हम देखना चाहते हैं। मेजबान टीम भारत शानदार फॉर्म में है लेकिन चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी टीमों के खिलाफ मजबूती से खेलना होगा। भारतीय टीम ने तीन बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। मेजबान टीम के पास दक्षिण कोरिया से आगे निकलने का मौका है, जिसके नाम भी तीन खिताब हैं।

आईपीएल 2027 मिनी नीलामी से पहले एलएसजी के पर्स में सबसे ज्यादा रकम, गुजरात के पास सबसे कम



नई दिल्ली,एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 के लिए खिलाड़ियों के रिटेंशन के बाद अब सभी 10 फ्रेंचाइजी की नजरें अगले महीने होने वाली मिनी नीलामी पर हैं। इस बार सभी 10 टीमों ने कुल 184 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिनमें 55 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। रिटेंशन के बाद फ्रेंचाइजी के पर्स में कुल 297.95 करोड़ रुपये बाकी हैं। सबसे ज्यादा पैसा लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के पास बचा है। फ्रेंचाइजी के पर्स में 47.45 करोड़ रुपये हैं। वहीं गुजरात टाइटंस के पास सबसे कम रकम बची है। उनके पास सिर्फ 8.75 करोड़ रुपये बचे हैं। आईपीएल 2027 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होगी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की आधिकारिक वेबसाइट पर बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस बार सभी 10 टीमों ने कुल 184 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिनमें 55 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। सभी फ्रेंचाइजी ने कुल मिलाकर 1,002.05 करोड़ खर्च किए हैं और अब नीलामी के लिए उनके पास कुल 297.95 करोड़ की रकम बची है। इन 10 टीमों में अभी भी 66 खिलाड़ियों की जगह खाली है, जिसमें 25 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट शामिल हैं। इससे फ्रेंचाइजी को अपनी टीम में और खिलाड़ी जोड़ने और अपने संयोजन को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।

गुजरात टाइटंस (जीटी) ने सबसे ज्यादा 22 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास सबसे ज्यादा 7 विदेशी खिलाड़ी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने 19-19 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स (18 खिलाड़ियों को रिटेन किया) नीलामी में सबसे ज्यादा 47.45 करोड़ की रकम के साथ उतरेगी। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (41.65 करोड़), सनराइजर्स हैदराबाद (40.15 करोड़) और दिल्ली कैपिटल्स (39.50 करोड़) का नंबर आता है। गुजरात टाइटंस के पास सबसे कम 8.75 करोड़ की रकम बची है और उनके पास 3 स्लॉट खाली हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)

रिटेन खिलाड़ी- अकील होसेन, अंशुल कंबोज, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, गुरजापनीत सिंह, जैक एडवर्ड्स (ट्रेड खिलाड़ी), जेमी ओवरटन, कार्तिक शर्मा, लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेड खिलाड़ी), मुकेश चौधरी, नूर अहमद, राहुल चाहर, रामकृष्ण घोष, रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सरफराज खान, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, उर्विल पटेल।

रिलीज खिलाड़ी: एमएस धोनी, मैट हेनरी, मैथ्यू शॉर्ट, जैक फॉल्क्स, कुलदीप यादव, प्रशांत वीर, मैकनील नोरोन्हा, अमन खान, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर, जबकि खलील अहमद और नाथन एलिस ट्रेड के जरिए बाहर हुए। वहीं एमएस धोनी सीएसके में मेंटर की भूमिका निभाएंगे।

बचा पर्स: 28.05 करोड़ रुपये 7 खाली स्लॉट: 6 7 विदेशी स्लॉट: 2

2. मुंबई इंडियंस (एमआई)

रिटेन खिलाड़ी: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, नमन धीर, रयान रिकेल्टन, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, राज बावा, मिचेल सैंटनर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा, अर्शदीप सिंह (ट्रेड इन)।

रिलीज खिलाड़ी: ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम गजनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इजहार, दानिश मालवर, मयंक मार्कंडे, मयंक रावत, महिपाल लोमरोर, रॉबिन मिंज, रुचित अहिर, कृष भगत, हार्दिक पांड्या (ट्रेड आउट)।

बचा पर्स: 32.6 करोड़ रुपये 7 खाली स्लॉट: 9 7 विदेशी स्लॉट: 2

3. दिल्ली कैपिटल्स (डीसी)

रिटेन खिलाड़ी: अक्षर पटेल, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, औकिब नबी, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, काइल जैमीसन, ऋषभ पंत (ट्रेड इन), जीशान अंसारी (ट्रेड इन)।

रिलीज खिलाड़ी: मिचेल स्टार्क, नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुश्मंथा चमीरा, रेहान अहमद, अजय मंडल, टी. नटराजन (ट्रेड आउट), कुलदीप यादव (ट्रेड आउट)।

बचा पर्स: 39.5 करोड़ रुपये 7 खाली स्लॉट: 9 7 विदेशी स्लॉट: 4

4. लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी)

रिटेन खिलाड़ी: मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, जोश इंग्लिस, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, मयंक यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, अर्शिन कुलकर्णी, कुलदीप यादव (ट्रेड इन), सैम करन (ट्रेड इन)।

रिलीज खिलाड़ी: आवेश खान, मैथ्यू ब्रीट्जके, एनरिक नॉर्टजे, जॉर्ज लिंडे, वानिंदु हसरंगा, नमन तिवारी, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत (ट्रेड आउट), मोहम्मद शमी (ट्रेड आउट), एम. सिद्धार्थ (ट्रेड आउट)।

बचा पर्स: 47.45 करोड़ रुपये 7 खाली स्लॉट: 7 7 विदेशी स्लॉट: 3

5. पंजाब किंग्स (पीबीकेएस)

रिटेन खिलाड़ी: श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मुशीर खान, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, सूर्यांश शेडगे, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, यश ठाकुर, व्यशाक विजयकुमार, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, हरनूर सिंह, हार्दिक पांड्या (ट्रेड इन)।

रिलीज खिलाड़ी: नेहाल वढेरा, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल ओवेन, पायला अविनाश, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, अर्शदीप सिंह (ट्रेड आउट)।

बचा पर्स: 18.6 करोड़ रुपये 7 खाली स्लॉट: 6 7 विदेशी स्लॉट: 2

6. राजस्थान रॉयल्स (आरआर)

रिटेन खिलाड़ी: रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, नांद्रे बर्गर, शुभम दुबे, अमन राव, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, यश राज पुंजा, जोफ्रा आर्चर, बृजेश शर्मा, संदीप शर्मा, सुशांत मिश्रा, मोहम्मद शमी (ट्रेड इन), एम. सिद्धार्थ (ट्रेड इन)।

रिलीज खिलाड़ी: शिमरोन हेटमायर, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, युधवीर सिंह, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, इमानजोत चहल, सैम करन (ट्रेड आउट)।

बचा पर्स: 27.05 करोड़ रुपये 7 खाली स्लॉट: 6 7 विदेशी स्लॉट: 3

7. सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच)

रिटेन खिलाड़ी: पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान मलिंगा, ब्रायडन कार्स, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, क्रेन्स फुलेत्रा, टी. नटराजन (ट्रेड इन), खलील अहमद (ट्रेड इन), नाथन एलिस (ट्रेड इन)।

रिलीज खिलाड़ी: ट्रैविस हेड, कामिंदु मेंडिस, जयदेव उनादकट, दिलशान मदुशंका, ओंकार टारमले, अमित कुमार, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्जी, डेविड पेन, आरएस अम्बरीश, हर्षल पटेल (ट्रेड आउट), जीशान अंसारी (ट्रेड आउट), लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेड आउट), जैक एडवर्ड्स (ट्रेड आउट)।

बचा पर्स: 40.15 करोड़ रुपये 7 खाली स्लॉट: 7 7 विदेशी स्लॉट: 3

8. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी)

रिटेन खिलाड़ी: रजत पाटीदार, विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, रसिख सलाम, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, कनिष्क चौहान, यश दयाल।

रिलीज खिलाड़ी: जैकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, विहान मल्होत्रा, स्वप्निल सिंह।

बचा पर्स: 14.15 करोड़ रुपये 7 खाली स्लॉट: 5 7 विदेशी स्लॉट: 1

9. गुजरात टाइटंस (जीटी)

रिटेन खिलाड़ी: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, आर. साई किशोर, मानव सुथार, राशिद खान, जयंत यादव, जेसन होल्डर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, अरशद खान, निशांत सिंधु, हर्षल पटेल (ट्रेड इन)।

रिलीज खिलाड़ी: ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया, शाहरुख खान, कॉनर एस्टरहुइजन, पृथ्वीराज यारा।

बचा पर्स: 8.75 करोड़ रुपये 7 खाली स्लॉट: 3 7 विदेशी स्लॉट: 2

10. कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)

रिटेन खिलाड़ी: कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, फिन एलन, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, टिम साइफर्ट, सार्थक रंजन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी।

रिलीज खिलाड़ी: अजिंक्य रहाणे, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कामरा, लुवनित सिसोदिया, मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, नवदीप सैनी, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, तेजस्वी सिंह, उमरान मलिक।

बचा पर्स: 41.65 करोड़ रुपये 7 खाली स्लॉट: 8 7 विदेशी स्लॉट: 3

भारत में टेनिस का रोमांच बढ़ाएगी वर्ल्ड लीग, पांचवें सीजन में कई दिग्गज खिलाड़ी दिखाएंगे दम

बेंगलुरु,एजेंसी। वर्ल्ड टेनिस लीग (डब्ल्यूटीएल) अपने पांचवें सीजन के लिए अंतरराष्ट्रीय टेनिस के कुछ सबसे बड़े नामों को बेंगलुरु लाने के लिए तैयार है। 16 खिलाड़ियों की सूची में पूर्व विश्व नंबर-3 एलिना स्वितोलिना, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बेलिंडा बेनसिक, पूर्व विश्व नंबर-1 करोलिना प्लिस्कोवा, विंबलडन फाइनलिस्ट निक किर्गियोस और दो बार के विंबलडन डबल्स चैंपियन हैरी हेलियोवारा मुख्य आकर्षण होंगे।

आइकॉनिक स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स द्वारा लाइसेंस प्राप्त और प्रबंधित यह लीग 17 से 20 दिसंबर तक बेंगलुरु के एसएम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। सीजन 5 में चार टीमें एक्रिक्स ईगल्स, गेम चेंजर्स फाल्कन्स, ऑसी मावेरिक्स काइट्स और वीबी रियल्टी हॉक्स हिस्सा लेंगी। इनमें आठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और भारत के आठ प्रमुख टेनिस खिलाड़ी एक साथ खेलेंगे। महिला वर्ग की अगुवाई यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना करेंगी, जो 20 बार की डब्ल्यूटीए सिंगल्स चैंपियन और 2018 डब्ल्यूटीए फाइनल्स की विजेता हैं और इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थीं। उनके साथ स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनसिक भी मुख्य आकर्षण होंगी, जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता था और 2025 में विंबलडन सेमीफाइनलिस्ट रही थीं। इस सूची में चेक गणराज्य की



करोलिना प्लिस्कोवा भी शामिल हैं, जो पूर्व विश्व नंबर-1 और दो बार की ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट हैं। स्पेन की पाउला बडोसा, जो पूर्व विश्व नंबर-2 और 2021 इंडियन वेल्स चैंपियन हैं, पिछले सीजन के बाद एक बार फिर इस लीग में वापसी कर रही हैं। पुरुष वर्ग का लाइन-अप भी उतना ही दमदार है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस बेंगलुरु के कोर्ट पर अपना जलवा बिखेरेंगे। 2022 के विंबलडन फाइनलिस्ट और उसी वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स चैंपियन रहे किर्गियोस के साथ कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक भी जुड़ेंगे, जो नौ बार के एटीपी खिताब विजेता हैं और जनवरी, 2026 में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग नंबर-10 पर पहुंचे थे। बेल्जियम के जिजौ बर्ग्स, जिन्होंने इस साल ईस्टबोर्न में अपना पहला एटीपी खिताब जीता और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा, जो दो बार के विंबलडन पुरुष डबल्स चैंपियन (2024 और 2026) हैं, अंतरराष्ट्रीय लाइन-अप को पूरा करते हैं। भारत के प्रतिनिधित्व में अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा प्रतिभाओं का मजबूत मिश्रण देखने को मिलेगा। क्ले कोर्ट पर एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी सुमित नागल, भारत के प्रमुख डबल्स खिलाड़ी युकी भांबरी के साथ वापसी कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर सुरेश भी टीम का हिस्सा होंगे। पूर्व एटीपी सिंगल्स फाइनलिस्ट और दो बार के एटीपी 250 डबल्स चैंपियन रामकुमार रामनाथन भी शामिल हैं।

भारतीय महिला लाइन-अप में 17 वर्षीय माया राजेश्वरन रेवती और श्रीवल्ली रश्मिका भामिदिपति की वापसी होगी, जो पिछले सीजन में भी खेली थीं। उनके साथ रुतुजा भोसले (जिन्होंने 2023 एशियाई खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीता था) और वैष्णवी अडकर (2026 में भारत की नंबर-1 महिला सिंगल्स खिलाड़ी) भी जुड़ेंगी। वर्ल्ड टेनिस लीग के सह-संस्थापक महेश भूपति ने एक बयान में कहा कि सीजन 5 के लिए एक साथ आ रहे खिलाड़ियों की गुणवत्ता इस लाइन-अप को बेहद रोमांचक बनाती है। हमारे पास ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट, एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, पूर्व विश्व नंबर-1 खिलाड़ी और एटीपी तथा डब्ल्यूटीए टूर के कुछ सबसे बेहतरीन नाम हैं।

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगा न्यूजीलैंड, टॉम लैथम ने बताई रणनीति

नई दिल्ली,एजेंसी। न्यूजीलैंड और भारत के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 19 नवंबर से खेला जाएगा। इस मैच से पहले मेजबान टीम के कप्तान टॉम लैथम ने अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर टीम की रणनीति का खुलासा किया है। आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वेलिंगटन में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले लैथम ने मीडिया से बातचीत की। लैथम के मुताबिक न्यूजीलैंड पहले टेस्ट में तीन तेज गेंदबाजों और एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतरेगा। न्यूजीलैंड के कप्तान ने बताया कि जैकब डफी इस अहम मुकाबले के लिए टीम में काइल जैमीसन, मैट हेनरी और बॉलिंग ऑलराउंडर नाथन स्मिथ के साथ जुड़ेंगे। लैथम ने कहा कि हम तीन तेज गेंदबाजों और एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के साथ खेलेंगे। हमारे पास कई बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं और अच्छी बात यह है कि सभी फिट होने की राह पर हैं।

उन्होंने टीम संयोजन को लेकर आगे कहा कि यह पहले से तय करना मुश्किल है कि खिलाड़ी कौन से मैच खेलेंगे, लेकिन हम इस बात को लेकर लचीला रुख अपना रहे हैं कि मैचों के दौरान क्या होगा और खिलाड़ियों पर कितना काम का बोझ (वर्कलोड) रहेगा। हम अगले छह-सात हफ्तों के लिए अपनी योजनाओं को लचीला रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अभी हमारा पूरा ध्यान इसी मैच (भारत के खिलाफ पहला टेस्ट) पर है। न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक



तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए इस मुकाबले में उतरेगी, जबकि भारतीय टीम चौथे स्थान पर है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ के लिहाज से काफी अहम होगी। अगले साल जून में इंग्लैंड के द ओवल में इस चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद न्यूजीलैंड को 9 दिसंबर से शुरू होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है। साल 2021 में पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने वाली न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर खिताबी मुकाबले में जगह बनाने की मजबूत दावेदार मानी जा रही है। हालांकि, कप्तान टॉम लैथम का कहना है कि फिलहाल टीम का ध्यान डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका या फाइनल की संभावनाओं पर नहीं, बल्कि अपने प्रदर्शन पर है। उन्होंने कहा, 'मेरा ध्यान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर नहीं है। हम उन चीजों पर ध्यान देंगे, जो हमारे नियंत्रण में हैं। हम अपनी रणनीति के मुताबिक क्रिकेट खेलेंगे और मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।'

एक नजर

मलेशिया में नेपाली श्रमिकों से ठगी के मामले में दो पूर्व मंत्रियों समेत छह गिरफ्तार

काठमांडू,एजेंसी। मलेशिया में वैदेशिक रोजगार के लिए जाने वाले नेपाली श्रमिकों से धोखाधड़ी कर वसूली गई रकम को गैरकानूनी तरीके से मलेशिया भेजने के फैसले में शामिल होने के आरोप में नेपाल के दो पूर्व मंत्रियों समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेरबहादुर कुँवर और रामेश्वर राय यादव शामिल हैं। इनके अलावा श्रम मंत्रालय के तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार प्रबंधन महाशाखा के तत्कालीन प्रमुख उमेश ढुंगाना और राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानून अधिकारी निर्मला गुरुङ को भी गिरफ्तार किया गया है। नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीआईबी) के अनुसार, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के पत्र और विकास रानाभाट सहित अन्य लोगों की शिकायत के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस के मुताबिक, काठमांडू जिला अदालत से 18 नवंबर को गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अनुमति लेने के बाद काठमांडू, ललितपुर और सर्लाही के विभिन्न स्थानों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और संगठित अपराध निवारण अधिनियम, 2010 के तहत जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, नेपाल और मलेशिया सरकार के बीच हुए समझौते के विपरीत अवैध तरीके से एकत्र की गई रकम में से 8 करोड़ 37 लाख 4 हजार 39 अमेरिकी डॉलर और 3 करोड़ 71 लाख 79 हजार 880 पाउंड स्टर्लिंग, यानी कुल 1 अरब 69 करोड़ 2 लाख 24 हजार 26 रुपये 76 पैसे मलेशिया भेजने का निर्णय लिया गया था। पुलिस का आरोप है कि समझौते के दायरे और कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विदेशी मुद्रा को अवैध रूप से विदेश भेजने के फैसले में इन अधिकारियों और पूर्व मंत्रियों की संलिप्तता थी। पुलिस के मुताबिक, नेपाली श्रमिकों के साथ संगठित तरीके से हो रही ठगी पर चुप्पी साधने, पीड़ितों को कानूनी राहत दिलाने के लिए पहल नहीं करने और अवैध रूप से एकत्र की गई रकम मलेशिया भेजने के फैसले में शामिल होने के आरोपों की जांच आगे बढ़ाई गई है।

उत्तर कोरिया योंगब्योन परमाणु परिसर में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का कर रहा विस्तार : आईएईए

वियना,एजेंसी। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में योंगब्योन परमाणु परिसर में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का विस्तार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ग्रोसी के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने योंगब्योन में अपने मूल यूरेनियम संवर्धन संयंत्र के साथ एक अतिरिक्त ढांचे का निर्माण किया है। आईएईए के 35 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तिमाही बैठक में उन्होंने बताया कि सितंबर 2026 के मध्य से इस संयंत्र के विस्तार का काम चल रहा था और अक्टूबर के अंत तक नया हिस्सा बाहरी रूप से पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का लगातार विस्तार गंभीर चिंता का विषय है। ग्रोसी ने यह भी कहा कि एजेंसी को योंगब्योन के पांच मेगावाट वाले परमाणु रिएक्टर के लगातार संचालित होने के संकेत मिले हैं। इस रिएक्टर का इस्तेमाल प्रयुक्त परमाणु ईंधन से प्लूटोनियम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उनके अनुसार, रिएक्टर संभवत: अपने सातवें विकिरण चक्र में है। इसके बाद प्रयुक्त ईंधन को निकालकर पुनर्प्रसंस्करण किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योंगब्योन में एक अन्य हल्का जल रिएक्टर भी अप्रैल से संचालित हो रहा है। आईएईए को 2009 में उत्तर कोरिया से अपने निरीक्षकों को निष्कासित किए जाने के बाद से वहां प्रत्यक्ष पहुंच नहीं मिली है। ऐसे में एजेंसी मुख्य रूप से उपग्रह तस्वीरों और अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर देश की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है।

ओडेसा में रूस का 'डबल-टैप' हमला, चार लोगों की मौत, बचावकर्मी भी बने निशाना

कीव। यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र पर रूसी हमलों में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हमले को 'बर्बर' बताते हुए आरोप लगाया कि रूसी सेना ने बचावकर्मियों और पुलिस अधिकारियों को भी निशाना बनाया। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि बचावकर्मियों और पुलिस अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद दोबारा हमले किए गए। इस तरह के हमलों को सैन्य भाषा में 'डबल-टैप' कहा जाता है, जिसमें पहले हमले के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंचे लोगों को निशाना बनाते हुए दूसरा हमला किया जाता है। जेलेंस्की ने इसे 'बर्बर और जानबूझकर किया गया हमला' करार दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात का एक और प्रमाण है कि रूस वास्तव में क्या चाहता है और कूटनीतिक प्रयासों को किस नजर से देखता है। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह किपर ने 'टेलीग्राम' पर बताया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल शहर के ऐतिहासिक केंद्र पर तीन बार हमले किए गए। उन्होंने कहा कि सुबह हुए रूसी हमलों में हताहतों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें चार लोगों की मौत हुई है। काला सागर के तट पर स्थित ओडेसा यूक्रेन का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। युद्ध शुरू होने के बाद से यह रूसी गोलाबारी और हवाई हमलों का सामना कर रहा है। शहर के बंदरगाह ढांचे और मालवाहक जहाजों को भी पहले निशाना बनाया जा चुका है।

पीएम बालेन्द्र शाह और भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला के बीच मुलाकात में भारत दौरे की तैयारियों पर हुई चर्चा

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और नेपाल में नवनियुक्त भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला के बीच बुधवार को मुलाकात हुई। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में दोपहर को दोनों के बीच मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री शाह ने सुधाकर दलेला को नेपाल के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त होने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। साथ ही उन्होंने नेपाल में आई रसुवा-भोटेकोशी बाढ़ के बाद भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री शाह ने अपनी आगामी भारत यात्रा की तैयारियों के बारे में भी राजदूत दलेला से जानकारी ली। इस दौरान भारतीय राजदूत दलेला ने कहा कि प्रधानमंत्री शाह की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मुलाकात ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री शाह की भारत यात्रा के एजेंडे तय हो चुके हैं और इस यात्रा को अधिक उपलब्धिमूलक बनाने के लिए दोनों देशों के संबंधित निकायों के बीच तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। मुलाकात में नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों को और मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। नेपाल के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त होकर आने के बाद सुधाकर दलेला इससे पहले विदेश सचिव अमृत बहादुर राई सहित नेपाल सरकार के विभिन्न मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने 17 नवंबर को नेपाल के बुनियादी ढांचा विकास मंत्री सुनील लम्साल, पर्यटन मंत्री खडकराज पौडेल (गनेश) और विदेश सचिव अमृत बहादुर राई से मुलाकात की थी।

ढाका में कपड़ा कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुलिस वाहन आग के हवाले, 300 गिरफ्तार

ढाका,एजेंसी। देश की राजधानी ढाका में कपड़ा कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। आज सुबह राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों और पुलिस के बीच कई स्थानों पर झड़पें हुई हैं। भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जवान देखते रहे और वाहन जलता रहा। पुलिस ने ताज हिंसा के सिलसिले में कम से कम 300 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार सुबह राजधानी के गाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान मलेकर बारी पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी गई। कपड़ा कर्मचारी 30,000 टका मासिक न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। यह कर्मचारी कुछ समय से आंदोलनरत हैं। आज कर्मचारियों ने ढाका-मयमनसिंह राजमार्ग को जाम कर दिया और पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। यह घटनाएं सुबह करीब 10:30 बजे गाजीपुर शहर के मलेकर बारी और साइनबोर्ड इलाकों में हुईं।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कई कंपनियों के कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचे। वह तय स्थान पर इकट्ठा हुए और राजमार्ग को जाम कर दिया। इससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने की कोशिश की। इससे स्थिति खराब हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। गाजीपुर इंडस्ट्रियल पुलिस-2 के अधीक्षक मोहम्मद अमजद हुसैन ने बताया कि सुबह स्थिति शांत थी। बाद में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। उन्होंने



कहा कि पुलिस, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और अंसार के जवानों के साथ मिलकर स्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए आंसू गैस के गोले और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के सावर और अशुलिया में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह कर्मचारियों ने दो जगह पर सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस को सड़क खाली कराने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस ने बताया कि इस विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में सावर और अशुलिया थानों में 24 मामले दर्ज किए गए हैं और तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप में लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस आंदोलन में कई बीड़ी फैक्टरियों के मजदूर भी शामिल हो गए हैं। अशुलिया थाना प्रभारी मोहम्मद तारिकुल इस्लाम ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने नरसिंहपुर में 'सारमिन ग्रुप' की एक फैक्टरी के सामने सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस को जाम खुलवाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ढाका जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध, संचालन और यातायात उत्तर) मो. जहांगीर आलम ने बताया कि सावर और आशुलिया की कुछ कपड़ा फैक्टरियों को बांग्लादेश श्रम कानून की धारा 13(1) के तहत बंद कर दिया गया है, जबकि अन्य में सामान्य छुट्टी घोषित कर दी गई है।

बालेन्द्र शाह के भारत दौरे में उठेगा चीनी ठेकेदारों के जलविद्युत प्रोजेक्टों से बिजली खरीद का मुद्दा, अपर तामाकोशी को मंजूरी दिलाने की मांग करेगा नेपाल

काठमांडू। नेपाल लंबे समय से इस बात की मांग करता रहा है कि भारत न केवल चीनी निवेश वाले, बल्कि चीनी ठेकेदारों द्वारा बनाए गए जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दे। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के भारत दौरे के दौरान नेपाल इस मांग को भारत के सामने रखेगा। साथ ही, 456 मेगावाट क्षमता वाली अपर तामाकोशी परियोजना सहित चीनी ठेकेदारों की भागीदारी में निर्मित अन्य जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली निर्यात की अनुमति देने की मांग करेगा। नेपाल लंबे समय से भारत को बिजली निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, 456 मेगावाट की अपर तामाकोशी सहित चीनी ठेकेदारों के माध्यम से निर्मित कई परियोजनाओं को अब तक भारतीय बाजार में बिजली बेचने की अनुमति नहीं मिल सकी है। परियोजनाओं में चीनी ठेकेदारों की भागीदारी को भारत ने मंजूरी प्रक्रिया में बाधा के रूप में लिया है। अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजना में चीनी कंपनी सिनो हाइड्रो ने सिविल निर्माण का काम किया था। हालांकि, परियोजना के हाइड्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े कार्य भारतीय कंपनियों ने किए थे। इसके बावजूद चीनी कंपनी की भागीदारी के कारण भारत ने इस परियोजना से बिजली निर्यात को मंजूरी नहीं दी है।

भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में सीमा पार बिजली आयात-निर्यात से संबंधित कार्यविधि जारी की थी। इसके तहत भारतीय बाजार में बिजली बेचने के लिए प्रत्येक जलविद्युत परियोजना को अलग-अलग मंजूरी लेनी पड़ती है। इस कार्यविधि में प्रावधान है कि भारत के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग समझौता नहीं करने वाले पड़ोसी तीसरे देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश अथवा नियंत्रण रखने वाली कंपनियों की परियोजनाओं से भारत बिजली नहीं खरीदेगा। वर्ष 2018 में जारी सीमा पार बिजली व्यापार संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार इस कार्यविधि की धारा 6.3 में ऐसा प्रावधान है। हालांकि, इसमें सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया है कि चीनी निवेश वाली सभी परियोजनाओं से बिजली नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन चीन और भारत के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता नहीं होने के कारण नेपाल में चीनी निवेश या नियंत्रण वाली परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। हालांकि, इस कार्यविधि में चीनी ठेकेदारों द्वारा निर्माण किए गए प्रोजेक्टों से बिजली खरीदने पर स्पष्ट रोक नहीं है।

बांग्लादेश में शेख हसीना के गृह जिला गोपालगंज में तनाव

ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश अवामी लीग की नेता और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में स्वदेश वापसी की घोषणा और सरकार के नकारात्मक रुख से हिंसा की लपटें उठने लगी है। गोपालगंज जिले में कल रात हुई हिंसा के बाद तुंगीपाड़ा उपजिला में तनाव बना हुआ है। सड़कों पर पेड़ों के बड़े-बड़े तने डाल दिए गए हैं। इससे उपजिला और आसपास के इलाकों के बीच सड़क संपर्क कट गया है।

गोपालगंज बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना का गृह क्षेत्र है। शेख हसीना का जन्मस्थान इसी जिले के तुंगीपाड़ा उपजिले में है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार कल रात निलफा बाजार में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के चार वाहनों को आग लगा दी गई थी। यह वाहन आज सुबह 9:00 बजे भी सुलग रहे थे। तुंगीपाड़ा उपजिला निर्वाही अधिकारी मो. दीदारुल आलम ने बताया, 'निलफा बाजार से तुंगीपाड़ा तक की पूरी सड़क पेड़ों के तनों से बंद कर दी गई हैं। हममें से कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि निलफा बाजार चौराहे से तुंगीपाड़ा तक लगभग 12 किलोमीटर लंबी सड़क पर कई जगहों पर पेड़ों के बड़े-बड़े तने पड़े हैं। इससे यातायात पूरी तरह ठप है। बताया जा रहा है कि ये तने पास की आरा मशीनों से लाकर सड़क पर डाले गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कल शाम को ही सड़क पर पेड़ों के तने डालकर रास्ता बंद कर दिया गया था। इस दौरान तुंगीपाड़ा की ओर जा रहे वाहनों और बीजीबी के बख्तरबंद वाहनों को निलफा बाजार में रोक लिया गया। इसके बाद चार वाहनों को आग लगा दी गई।

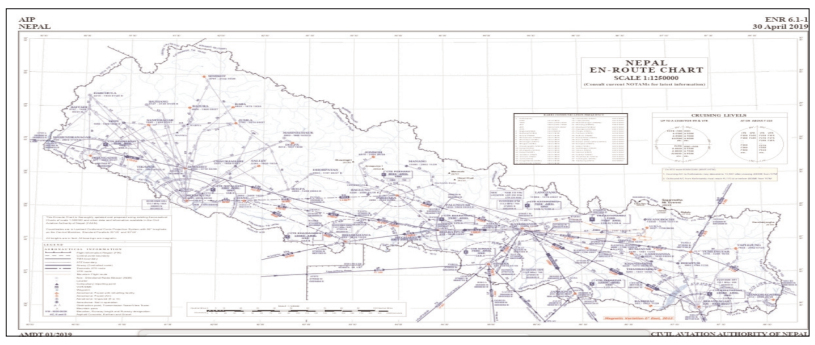
निलफा बाजार इलाके में एक भोजनालय के कर्मचारी हसन गाजी ने बताया कि कल शाम वहां पुलिस की एक गाड़ी को भी रोका गया था। उन्होंने कहा, 'कारोबार लगभग पूरी तरह ठप हो गया है। फिर भी, हम चाहते हैं कि देश में हालात बेहतर हों। यूनुस की सरकार में भी हमारे हालात अच्छे नहीं थे और बीएनपी सरकार में भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए हालात सुधरेंगे। तुंगीपाड़ा निवासी बिथी मजूमदार ने कहा कि लोग शांति चाहते हैं और हिंसा की ऐसी घटनाओं का अंत चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'हम डर के साये में जी रहे हैं। यह लोगों के हित में होगा कि सभी राजनीतिक दल बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझा लें।

नेपाल को उत्तराखंड का एयर रूट देने को तैयार हुआ भारत, बालेन्द्र शाह के दौरे में होगा समझौता

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल को 12 वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग (एयर रूट) उपलब्ध कराने के लिए भारत तैयार होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की आगामी भारत यात्रा के दौरान नेपाल की ओर से उठाए जाने वाले प्रमुख समझौते में एयर रूट का मामला शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री शाह 22 नवंबर को भारत यात्रा पर जाने की तैयारी में हैं। एयर रूट के मुद्दे पर चर्चा के लिए संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख जयनारायण आचार्य, विदेश मंत्रालय के सहसचिव एवं दक्षिण एशिया महाशाखा प्रमुख गेहेन्द्र राजभण्डारी और नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक मुकेश डंगोल नई दिल्ली पहुंचे थे। नेपाल विशेष रूप से भैरहवा, नेपालगंज, महेन्द्रनगर और जनकपुर के लिए अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध कराने की मांग भारत से करता रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में हुई बातचीत के बाद भारत उत्तराखंड के बनवासा होते हुए नेपाल के महेन्द्रनगर के रास्ते विमानों को प्रवेश देने के लिए सकारात्मक दिखाई दिया है। दिल्ली से लौटे महानिदेशक डंगोल ने कहा, 'बातचीत काफी सकारात्मक रही है। हमने अपनी जरूरतों और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की है। इस पर उच्चस्तरीय बातचीत के बाद निर्णय होगा। महेन्द्रनगर से एयर रूट देने के मुद्दे पर भारतीय पक्ष काफी सकारात्मक दिखा है।

एक ही एयर रूट पर निर्भर हैं नेपाल की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

भारत की ओर से अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण नेपाल की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल एक ही प्रवेश बिंदु पर निर्भर हैं। कई विमानों को बिहार के रक्सौल से नेपाल के सिमरा के रास्ते नेपाल में प्रवेश करना या बाहर निकलना पड़ता है। इससे हवाई यातायात के प्रबंधन में चुनौतियां पैदा होती हैं। पश्चिमी देशों और मध्य पूर्व से आने वाले विमानों को भैरहवा या महेन्द्रनगर के रास्ते सीधे नेपाल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऐसे विमानों को लंबा चक्कर लगाकर सिमरा के रास्ते नेपाल आना पड़ता है। इस वजह से उड़ान का समय 25 मिनट से अधिक बढ़ जाता है और ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, यदि अंतरराष्ट्रीय विमानों को महेन्द्रनगर के रास्ते नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है तो भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल, पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल और काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल के लिए उड़ानों का संचालन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।



फिलहाल गौतम बुद्ध और पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थलों पर उतरने वाले विमानों को भी सिमरा के रास्ते लंबा चक्कर लगाकर पहुंचना पड़ता है। इससे उड़ान का समय 20 से 25 मिनट तक बढ़ जाता है। अतिरिक्त समय और ईंधन खर्च के कारण विदेशी विमानन कंपनियां भी इन दोनों अंतरराष्ट्रीय विमानस्थलों के लिए अपनी उड़ानों का विस्तार करने में रुचि नहीं दिखा रही हैं। नेपाल का मानना है कि महेन्द्रनगर के रास्ते नया हवाई प्रवेश मार्ग मिलने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का समय और परिचालन खर्च कम होगा। साथ ही, भैरहवा और पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थलों के संचालन तथा वहां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार को भी बढ़ावा मिल सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण के समय इस पर समझौता हो सकता है। खनाल ने कहा कि भारत के सकारात्मक रुख से हम आशावादी हैं कि इस बार कम से कम एक अतिरिक्त हवाई रूट पर समझौता हो जाएगा।

लाहौर में पुलिस ने पीटीआई के तीन नेताओं को हाई कोर्ट से बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया

इस्लामाबाद,एजेंसी। कई साल से रावलपिंडी की जेल में बंद अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता तैमूर सलीम झागरा, कामरान बंगश और इरफान सलीम को मंगलवार को पेशावर उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई को हुए हमले के सिलसिले में की गई है।

द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी के समय हाई कोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशंस) फरहान खान अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। पुलिस ने बताया कि तीनों नेता रेडियो पाकिस्तान हमले के मामले में आतंकवादरोधी अदालत के जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद अंतरिम जमानत की मांग करने हाई कोर्ट पहुंचे थे। हिरासत में लिए जाने से पहले वे हाई कोर्ट के बार रूम में मौजूद थे। हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की याचिकाओं को मंजूर कर लिया था। गौरतलब है कि रेडियो पाकिस्तान हमले के मामले में आतंकवादरोधी अदालत द्वारा मांगी गई पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट में 9 मई 2023 की घटनाओं से जुड़े फुटेज में सलीम सहित कई पीटीआई नेताओं की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। लैब ने पेशावर पुलिस के अनुरोध पर एक यूएसबी डिवाइस में दी गई 16 वीडियो क्लिप की जांच की। विश्लेषण में इन



नेताओं की प्रोफाइल तस्वीरों और फुटेज में दिख रहे व्यक्तियों के बीच समानताएं पाई गईं। रिपोर्ट में दो वीडियो क्लिप में छेड़छाड़ के सबूत भी मिले हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के अलावा इरफान सलीम से जुड़े हैं। यह फॉरेंसिक जांच 19 से 23 दिसंबर 2025 के बीच की गई।

बताया गया है कि 9 मई को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो के वारंट के तहत इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस ऐतिहासिक इमारत पर हमला कर दिया। खान की गिरफ्तारी से पार्टी कार्यकर्ता भड़क गए और देश के कई शहरों में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें सैन्य प्रतिष्ठान भी शामिल थे। पेशावर भी उन शहरों में से एक है जहां तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने रेडियो पाकिस्तान की ऐतिहासिक इमारत पर धावा बोला। जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद उन्होंने इमारत में आग लगा दी। इस भीषण आग में कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और अन्य बेशकीमती चीजें जलकर राख हो गईं।

बालेन्द्र शाह के भारत दौरे पर नेपाल फिर उठाएगा धामरा और मुंद्रा बंदरगाह तक पहुंच का मुद्दा

काठमांडू,एजेंसी। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा के दौरान नेपाल तीसरे देशों के साथ आयात-निर्यात के लिए एक बार फिर भारत के ओडिशा और गुजरात स्थित दो बंदरगाहों तक पहुंच देने का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहा है। भारत ने वर्ष 2019 में ओडिशा के धामरा और गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह का इस्तेमाल तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए करने पर सहमति दी थी। हालांकि, अब तक इस सहमति को लागू करने के लिए व्यापार एवं पारगमन संधि में संशोधन नहीं हो सका है। इस बार नेपाल आयात-निर्यात को सुगम बनाने के उद्देश्य से भारत से इन दोनों बंदरगाहों तक पहुंच देने की मांग फिर से उठाने जा रहा है।

नेपाल का निजी क्षेत्र लंबे समय से कहता आ रहा है कि धामरा और मुंद्रा दोनों बंदरगाहों का प्रबंधन निजी क्षेत्र के अडानी समूह के पास होने के कारण इनके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना अधिक सुविधाजनक होगा। प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के एजेंडे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में व्यस्त विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा, 'हम बंदरगाहों के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने के लिए यह मांग उठाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भारत के कोलकाता, हल्दिया और विशाखापत्तनम बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों को एक ही बंदरगाह व्यवस्था के रूप में देखता है। इसकी वजह यह है कि दोनों बंदरगाह एक ही समुद्री मार्ग पर स्थित हैं। कोलकाता में छोटे जहाज आते हैं, जबकि हल्दिया में बड़े जहाजों को लाया जाता है। इसके अलावा नेपाल को आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से भी तीसरे देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति है। नेपाल लंबे समय से इन तीन बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों के इस्तेमाल की अनुमति मांगता रहा है। धामरा और मुंद्रा दोनों ही बंदरगाहों पर बड़े समुद्री जहाज पहुंच सकते हैं। नेपाल को इन बंदरगाहों तक पहुंच मिलने से सामान के आयात और निर्यात में समय तथा लागत दोनों की बचत हो सकती है। यदि भारत गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह तक नेपाल को पहुंच देता है तो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से होने वाली माल ढुलाई अधिक आसान हो जाएगी। वहीं, ओडिशा के धामरा बंदरगाह के इस्तेमाल से पश्चिम एशियाई देशों से सामान लाने में सुविधा होगी। वीरगंज से धामरा बंदरगाह की दूरी लगभग 950 किलोमीटर है। कोलकाता बंदरगाह में समुद्र की गहराई कम होने के कारण बड़े मालवाहक जहाज सीधे नहीं पहुंच पाते। इसके चलते सामान की ढुलाई में अतिरिक्त समय और खर्च लगता है। इसके विपरीत, धामरा एक आधुनिक और गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है, जहां बड़े मालवाहक जहाज सीधे पहुंच सकते हैं। यह विशाखापत्तनम की तुलना में नेपाल की सीमा के अधिक नजदीक भी है। दूसरी ओर, मुंद्रा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बड़ा व्यावसायिक बंदरगाह है। यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका से आने वाले जहाज सीधे मुंद्रा पहुंच सकते हैं। इससे जहाजों को भारत के दक्षिणी हिस्से का चक्कर लगाकर कोलकाता या विशाखापत्तनम पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एक नजर

सांसद ने आग प्रभावित परिवारों से की मुलाकात



इटानगर,एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने कुरुंग कुमे जिले के पारसी-पारलो में आग से प्रभावित परिवारों से आज मुलाकात की। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने और नुकसान का आकलन करने के लिए राहत शिविर में प्रभावित परिवारों से बातचीत की। इस दौरान, तागाक ने उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने इस दुखद घटना में अपने अपनों को खो दिया। इस घटना में चार लोगों की जान चली गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पेमा खांडू की ओर से भी शोक व्यक्त किया। सांसद ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी। तत्काल राहत के तौर पर, प्रभावित परिवारों को चावल, कंबल और बर्तन जैसी जरूरी चीजें दी गईं, साथ ही कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। जान गंवाने वाले चार लोगों के परिवारों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी गई, जबकि जिन परिवारों के घर आग में पूरी तरह जल गए थे, उन्हें 25-25 हजार रुपये की सहायता दी गई। सांसद के साथ भाजपा कुरुंग कुमे जिला अध्यक्ष फासांग बांघी, जिला परिषद अध्यक्ष बाके यामा यांगदा, पारसी-पारलो के सहयोग उपयोग नबाम ताजिक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। तागाक ने इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता जताई और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस संकट से उबरने और अपना जीवन फिर से बसाने में उन्हें हर संभव मदद और समर्थन दिया जाएगा। आग की इस घटना में एक ही परिवार के चार लोगों (जिनमें तीन बच्चे और एक महिला शामिल हैं) की मौत हो गई और लगभग 25 घर जलकर राख हो गए।

इटानगर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता हुए शामिल

इटानगर। अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज इटानगर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कालिंग मोयोंग और मंत्री बालो राजा के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने न्योकुम लापांग ग्राउंड से इंदिरा गांधी पार्क तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ नारों वाले बैनर और पोस्टर थाम रखे थे, जिनमें 'लोकतंत्र बचाओ' का संदेश दिया गया था। पदयात्रा के बाद, इंदिरा गांधी पार्क में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान केवल भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राज्य में एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगियों की एक संयुक्त पहल है। इस अभियान में एनडीए के विभिन्न घटक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाजपा नेताओं के साथ हिस्सा लिया, जो उनकी एकजुटता और समर्थन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए, उन्होंने पिछले 12 वर्षों में भारत के विकास, आर्थिक प्रगति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए खांडू ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहा है और लगातार चुनावी हार के बाद युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

झारखंड कैबिनेट के 41 फैसलों पर लगी मुहर, राज्य कर्मियों का डीए 60% से बढ़कर 63% हुआ

रांची,एजेंसी। झारखंड सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह निर्णय बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में राज्य के कर्मियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिलता था, जिसे बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया है। यह वृद्धि एक जुलाई 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में एक जुलाई, 2026 के प्रभाव से लागू होगी। वहीं कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में भी एक जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार के पेंशनधारियों अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में भी एक जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

वहीं राज्य सरकार के अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में एक जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई और इसी अवधि से पुनरीक्षित राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।

पलामू में डिग्री कॉलेज के लिए 37.36 करोड की मंजूरी

कैबिनेट ने पलामू स्थित नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय अंतर्गत विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी।

वर्ष 2027 में होंगे 23 सरकारी अवकाश

वर्ष 2027 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंको में कुल 23 अवकाश होंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, मिलाद-उन-नवी, गुरूनानक जयंति 14 नवंबर को रविवार का अवकाश पडने के कारण तिथि के लिए अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है। हालांकि वैसे प्रतिष्ठान जहां रविवार सामान्य कार्यदिवस होता है ऐसे संस्थानों में उक्त तिथि को अवकाश रहेगा। ये अवकाश एनआई एक्ट के तहत घोषित किए गए हैं।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- भगन मुंडा सहित अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के पालन में सभी याचिकाकर्तृताओं (18 याचिकाकर्तृता एवं याचिकाकर्तृता संख्या-02 के दिवंगत पति सहित कुल 19) को ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत उपर्युक्त कर्मियों को पे बैंड-1 5200-20200 रुपये के स्थान पर पे बैंड-1 5200-20200 रुपये देने की स्वीकृति दी गई।

- पाकुड़ जिले के बहिरग्राम (पीडब्यूम डी रोड) झिकेरहटटी-कांकरबोना-संकरघाट से इस्लामपुर 8.300 किमी सडक को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए कुल 44.52 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- सरायकेला-खरसावां जिला के पातकुम - ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ 16.76 किमी सडक निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- जामताड़ा जिले के करमाटांड बाजार बाईपास पथ 7.170 किमी सडक के निर्माण कार्य के लिए 85.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- रांची जिला के मुडमा चौक (एनएच-75 पर)- सुरसा मसमानो-पाली (ईटकी-ब्राम्बे पथ पर) पथ एवं बास्की-तुतियांबे सडक 9.752 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 28.77 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन करते हुए निबंधन (झारखण्ड संशोधन) विधेयक-2026 की स्वीकृति दी गई।

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024 को समाप्त अवधि की रिपोर्ट (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को झारखण्ड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

आतंकवाद जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन : उपराज्यपाल

जम्मू,एजेंसी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद जम्मू-कश्मीर में शांति, स्थिरता और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद और अलगाववाद को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर में 74 प्रशिक्षु अधिकारियों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने विश्वास जताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षाबल बचे हुए आतंकवादी नेटवर्कों को नष्ट करने के लिए पूरे संकल्प के साथ अपने प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उपराज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और पास आउट होने वाले दल की सलामी ली। नए प्रशिक्षित अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वर्दी पहनना केवल कोई रैंक या पद पाना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की सेवा करने, नागरिकों की रक्षा करने और संविधान को बनाए रखने का एक गंभीर संकल्प है। इस बैच में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के 25 अधिकारी, पुलिस उप-निरीक्षक (पीएसआई) के 36 अधिकारी और वन संरक्षण बल के 13 सहायक निदेशक शामिल थे। 25 डीएसपी में से 20 पुरुष और 5 महिलाएं हैं जबकि पीएसआई बैच में 25 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। वन संरक्षण बल के बैच में 3 पुरुष और 10 महिलाएं हैं।

शुरुआत में सिन्हा ने पुलिस शहीद रसपाल कुमार और बॉबी चंद को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र तथा जम्मू-कश्मीर की सेवा में उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। उन्होंने शहीद परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन और पूरा देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि उनके सम्मान, सुरक्षा और उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। शहीदों के परिवारों को प्रेरणा और राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, समर्पण और राष्ट्र सेवा के मूल्यों के लिए प्रेरित करता रहेगा। नए प्रशिक्षित अधिकारियों से जम्मू-कश्मीर पुलिस की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने का आह्वान करते हुए सिन्हा ने उनसे आग्रह किया कि वे पूरी ईमानदारी, साहस, अनुशासन और पेशेवर तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी समाज और राष्ट्र के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी लाती है।

पुणे में 19 से 22 दिसंबर तक होगा भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विश्व बंधु भारत' के विजन के अनुरूप भारतीय विज्ञान अब केवल देश की जरूरतों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए समाधान प्रस्तुत कर रहा है। भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां वैश्विक वैज्ञानिक व्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की ओर से विकसित स्वदेशी शोध किट को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) लेकर गए थे। वहां किए गए प्रयोगों के नतीजे पूरी दुनिया के लिए उपयोगी साबित होंगे।

वे बुधवार को भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) 2026 के 12वें संस्करण का कर्टेन रेजर लॉन्च करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट और ब्रोशर का भी अनावरण किया। पुणे में 19 से 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस चार दिवसीय महोत्सव की थीम 'भारत का विज्ञान, विश्व का भविष्य' रखी गई है। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के विज्ञान आयोजनों के स्वरूप में व्यापक बदलाव किया गया है। सरकार ने बिखरे हुए और एक जैसे आयोजनों के स्थान पर दो अलग-अलग राष्ट्रीय मंच विकसित किए हैं। इनमें नई दिल्ली में आयोजित होने वाला इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ईएसटीआईसी) और देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित होने वाला भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शामिल है। ईएसटीआईसी में 13 से अधिक मंत्रालयों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं की भागीदारी होती है, जबकि आईआईएसएफ का उद्देश्य विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना और उसमें जनभागीदारी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़, हैदराबाद, गोवा और दिल्ली के बाद पहली बार पुणे में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पुणे का मजबूत शैक्षणिक, औद्योगिक और अनुसंधान तंत्र इस आयोजन को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि आईआईएसएफ 2026 में जीन एडिटिंग, एंटीबॉडी, इंसुलिन उत्पादन, ऊर्जा के नए स्रोत और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी जैसे विषयों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। महोत्सव में 2001 के नोबेल पुरस्कार विजेता सर टिम हंट का विशेष व्याख्यान भी होगा। युवाओं, बच्चों, महिलाओं, स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें बी2बी बैठकें, हैकाथॉन, साइंस सफारी और वैज्ञानिकों के साथ संवाद के अवसर शामिल हैं।

दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा पर भारत-यूएन में मंथन, प्रशस्त ऐप से 6 करोड़ से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग

नई दिल्ली,एजेंसी। दिव्यांग बच्चों को समान और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में भारत सरकार की पहल को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव टी. के. अनिल कुमार ने 17 नवंबर को नई दिल्ली में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के साथ संवादात्मक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, स्कूलों में समावेशी वातावरण तैयार करने और दिव्यांग बच्चों को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल के सामने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी भी साझा की।



बैठक में शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रमुखता से रखा। इसके तहत बच्चों में दिव्यांगता की शुरुआती पहचान, उनकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत सहायता, स्कूलों में सुगम्यता, चिकित्सकीय एवं चिकित्सीय पुनर्वास संबंधी हस्तक्षेप, कौशल विकास और परीक्षा से जुड़ी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था को बच्चों के जीवन के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शुरुआती शिक्षा से लेकर आगे की पढ़ाई तक जरूरी सहयोग मिल सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया। बैठक में प्रशस्त पहल को भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया। प्रशस्त एक दिव्यांगता स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है, जिसके माध्यम से 3 से 18 वर्ष तक के स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की शुरुआती पहचान की जा सकती है। मंत्रालय के मुताबिक, प्रशस्त 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन को नया रूप देकर इसे एकीकृत किया गया है। इससे शिक्षकों के लिए शुरुआती स्क्रीनिंग की प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो गई है।

पहले जिस प्रक्रिया में शिक्षकों को लगभग तीन दिन लगते थे, वह अब महज 15 मिनट में पूरी की जा सकती है। अक्टूबर 2026 तक इस पहल के तहत 6 करोड़ से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 7.26 लाख से अधिक स्कूल प्रशस्त पोर्टल पर जुड़ चुके हैं और 79 लाख से अधिक शिक्षकों को इस संबंध में जागरूक एवं प्रशिक्षित किया गया है। इस बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास ने दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित राजकीय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। यहां उन्होंने समग्र शिक्षा योजना के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और समावेशी शिक्षा से जुड़े प्रयासों का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल में बनाए गए रिसोर्स रूम का निरीक्षण किया, जहां विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएं और सहायता तंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों से भी बातचीत की और स्कूलों में मिल रही सुविधाओं तथा उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। इस संवादात्मक सत्र में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेने से बचें: स्वास्थ्य सचिव

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में विश्व एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) जागरूकता सप्ताह 2026 के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 18 से 24 नवंबर तक चलने वाले इस सप्ताह के माध्यम से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने और इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आज सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने मौजूद सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। दवाओं के गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के कारण जीवन बचाने वाली दवाओं का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। यदि इस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो सामान्य संक्रमणों का इलाज भी मुश्किल हो सकता है और चिकित्सा क्षेत्र में दशकों की प्रगति प्रभावित हो सकती है।

इस वर्ष की थीम 'वन हेल्थ, वन एक्शन: प्रिवेंट एएमआर नाउ' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एएमआर से निपटने के लिए मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पौधों, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण को एक साथ ध्यान में रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन हेल्थ विजन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के अनुचित इस्तेमाल से दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और यह समस्या तेजी



से फैल सकती है। इसलिए सभी संबंधित क्षेत्रों के बीच समन्वय जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार ने एएमआर पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नवंबर 2025 में राष्ट्रीय एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कार्ययोजना 2.0 (2025-2029) की शुरुआत की थी। इस कार्ययोजना में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, संक्रमण की रोकथाम, एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के जिम्मेदार इस्तेमाल, शोध और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय एएमआर नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के समन्वय से किया जा रहा है। इसके तहत एएमआर की निगरानी के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने, अस्पतालों में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, दवाओं के उचित इस्तेमाल तथा जन-जागरूकता पर काम किया जा रहा है।

कार्यक्रम में शामिल विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर चिंता जताई कि भारत में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की आधे से अधिक बिक्री बिना डॉक्टर के पर्चे के होती है। वहीं, बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) में लिखी जाने वाली करीब आधी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन अनुचित पाए जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए देशभर में जागरूकता अभियान चलाने और बिना वैध पर्चे के एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री रोकने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दवाओं और एक्सपायरी एंटीबायोटिक का सुरक्षित निस्तारण, मेडिकल दुकानों पर बिना पर्चे एंटीमाइक्रोबियल दवाएं नहीं बेचने संबंधी कानूनी चेतावनी प्रदर्शित करने, घटिया और नकली दवाओं के उत्पादन पर रोक लगाने तथा पशु चिकित्सा में एंटीबायोटिक के उचित इस्तेमाल को बढ़ावा देने जैसे उपायों पर भी चर्चा हुई। खाद्य उत्पादन से जुड़े पशुओं में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), पशुपालन विभाग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ड्रगिस्ट्स एंड केमिस्ट्स के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों से एएमआर के प्रति जागरूकता का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान किया। विश्व एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह हर साल 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आम लोगों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं तथा वन हेल्थ से जुड़े सभी पक्षों को इसके प्रसार को रोकने के लिए जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

अहमदाबाद में किसान कार्यशाला: आधुनिक कृषि तकनीक और उन्नत फसलों की मांग

अहमदाबाद,एजेंसी। गुजरात के किसानों ने बुधवार को आयोजित एक मीडिया कार्यशाला में कृषि क्षेत्र में विज्ञान-आधारित नीतियों और नई पीढ़ी की आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों तक पहुंच की जोरदार मांग की है। राष्ट्रीय किसान अधिकार मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों ने कहा कि देश दो दशक पुरानी तकनीक के सहारे नहीं रह सकता।



गुजरात उन राज्यों में शामिल था जहां वर्ष 2002 में बीटी कपास को सबसे पहले मंजूरी मिली थी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इसके बाद देश में कपास की पैदावार में भारी बढ़ोतरी हुई थी और भारत एक निर्यातक के रूप में उभरा था। हालांकि, तब से लेकर अब तक किसानों के पास कोई नया उन्नत विकल्प नहीं आया है। किसानों का कहना है कि गुलाबी सुंडी (कीट), अनिश्चित मौसम और बढ़ती लागत के कारण अब बेहतर कृषि गुणों वाली उन्नत तकनीकों की सख्त आवश्यकता है।

सिमरी गांव के एक किसान प्रकाश पुनामभाई पटेल ने बताया कि बीटी कपास ने खेती की दिशा बदली थी, लेकिन आज किसानों के सामने नई चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए बेहतर फसल किस्मों की जरूरत है। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. विजय कुमार ने कहा कि मुख्य सवाल यह नहीं होना चाहिए कि तकनीक का उपयोग किया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि इसे जिम्मेदारी से कैसे परखा जाए और कृषि की जरूरतों के अनुसार कैसे लागू किया जाए। चाणस्मा के किसान मुकेश कांतिलाल पटेल ने जोर दिया कि यदि किसानों को सही मार्गदर्शन मिले, तो वे ऐसी तकनीकों को अपनाएंगे जो उत्पादकता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कृषि नीतियों को विज्ञान के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। कार्यशाला में वक्ताओं ने बताया कि विनियामक अनिश्चितता इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। बीटी बैंगन और जीएम सरसों जैसी फसलें लंबे समय से प्रशासनिक और अदालती अड़चनों के बीच अटकी हुई हैं। इसके अलावा, राज्यों से मिलने वाली अनुमति में देरी के कारण परीक्षण भी प्रभावित होते हैं। कार्यक्रम के अंत में किसानों और विशेषज्ञों ने मांग की कि एक पारदर्शी और विज्ञान-आधारित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो इन तकनीकों का कड़ाई से मूल्यांकन करे और सुरक्षा मानकों पर खरी उतरने पर किसानों को बिना किसी देरी के उपलब्ध कराए, ताकि भारतीय कृषि वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत हो सके।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)